सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

दिशा निर्देश

Guidelines
on
Member of Parliament
Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

Government of India

Ministry of Statistics and Programme Implementation

Sardar Patel Bhawan, New Delhi-110001

Website : www.mplads.nic.in

अप्रैल, 2002
April, 2002

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
दिशा निर्देश
Guidelines
on
Member of Parliament
Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Statistics and Programme Implementation
Sardar Patel Bhawan, New Delhi-110001

Website : www.mplads.nic.in

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो)
योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्रबोधन व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश

योजना

1.1 संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे विकासात्मक निर्माण कार्यों को करवाने हेतु उनके निर्वाचन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा अक्सर अनुरोध किया जाता रहा है । इसलिए, सांसदों ने मांग की थी कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सक्षम होना चाहिए । इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधान मंत्री जी द्वारा 23 दिसंबर, 1993 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की गई । बाद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की योजना संकल्पना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फरवरी, 1994 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिसने आरंभ में इस योजना को संभाला था । इस मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 1994 में इन दिशा निर्देशों का संशोधन किया गया । इन दिशा निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने सांसदों एवं अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रचालन ब्यौरे के संबंध में समय–समय पर परिपत्र जारी किए । फरवरी, 1997 तथा सितंबर, 1999 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए । तत्पश्चात् दिशा निर्देशों के इन प्रावधानों पर समय–समय पर संशोधन जारी किए गए। यह दिशा निर्देश संशोधनों को सम्मिलित करते हुए जारी किए गए हैं ।

1.2 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य, जिलाधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तक की लागत वाले निर्माण कार्यों को करवाए जाने का सुझाव दे सकता है । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य जो कि संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राज्य से वे चुन कर आए/आई हैं, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कर सकते/सकती हैं । लोकसभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य अपनी पसंद के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु देश में कहीं भी एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते/सकती हैं। वर्ष 1998–99 से प्रति सांसद आबंटन बढ़कर प्रति वर्ष 2 करोड़ रु0 हो गया है ।

1.3 सांसद देश में कहीं भी प्रत्येक प्रचंड प्राकृतिक आपदा के समय दिशा निर्देशों में अनुमेय परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों के बाहर 10 लाख रु0 तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 प्रत्येक संसद सदस्य संबंधित जिलाधिकारी को अपनी पसंद के निर्माण कार्यों का ब्यौरा देंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित कराएंगे, यानि जिलाधिकारी दिशा निर्देशों के अधीन रहकर राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे । जहां तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन सांसदों की पसंद के अनुसार निगमों, नगरपालिकाओं आदि के आयुक्तों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों या सम्बद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से करवाया जा सकता है । कार्यान्वयन अभिकरणों में सरकारी या पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रसिद्ध गैर–सरकारी संस्थाएं आ सकतीं हैं, जिन्हें जिलाधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन करवाने में सक्षम समझते हों । इन कार्यों में निजी ठेकेदारों को लगाना वर्जित है, जहां पर भी विद्यमान दिशा निर्देशों में इसके लिए अनुमति नहीं है । लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है जो प्रभाग आवश्यक रुप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते किंतु जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम हैं, उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण आवास विभाग/स्कंध, आवास बोर्ड, विद्युत बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण आदि । जिलाधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कोई खास कार्य निष्पादित किया जाना है ।

MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)

GUIDELINES ON SCHEME CONCEPT, IMPLEMENTATION AND MONITORING.

The Scheme

1.1 Members of Parliament are approached by their Constituents, quite often, for small works of capital nature to be done in their constituencies. Hence, there was a demand made by MPs that they should be able to recommend works to be done in their constituencies. Considering these suggestions, the Prime Minister announced in Parliament on 23rd December, 1993, the " Member of Parliament Local Area Development Scheme". Detailed guidelines on the Scheme concept, implementation and monitoring of MPLADS were subsequently issued by the Ministry of Rural Development in February, 1994 who initially handled the Scheme. The guidelines were revised in December, 1994 by this Ministry. Pursuant to these guidelines, the Ministry issued Circulars, from time to time, on matters relating to operational details, based on suggestions received from Members of Parliament and others. Revised Guidelines were issued in February, 1997 and September, 1999. Thereafter, amendments to some provisions of the guidelines were issued from time to time. These guidelines are issued after incorporating amendments.

1.2 Under this scheme, each MP will have the choice to suggest to the Head of the District works to the tune of Rs.1 crore per year, to be taken up in his/her constituency. Elected Members of Rajya Sabha representing the whole of the State as they do, may select works for implementation in one or more District(s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more Districts, anywhere in the country. The allocation per MP per year stands increased to Rs.2 crores from the year 1998-1999.

1.3 MPs can also recommend works outside their constituencies/states for construction of assets that are permissible in the guidelines, for rehabilitation measures in the event of "natural calamity of rare severity" in any part of the country for an amount not exceeding Rs. 10 lakhs, for each calamity.

FEATURES OF THE SCHEME

2.1 Each MP will give a choice of works to the concerned Head of the District who will get them implemented by following the established procedures, that is, he may be guided by the procedure laid down by the State Government subject to these Guidelines. In regard to works in urban areas their implementation can be done through Commissioners/Chief Executive Officers of Corporations, Municipalities, etc., or through the Heads of District concerned as per the option of the MPs. Implementation agencies can be either Government or Panchayati Raj institutions or any other reputed non-governmental organisation who may be considered by the District Head as capable of implementing the works satisfactorily. Engagement of private contractors is prohibited, wherever extant Guidelines do not permit such engagement. For purposes of execution of works through Public Works Department (PWD), wings not necessarily exclusively dealing with civil construction, but having competence in civil construction can be engaged-like for example, Public Health Engineering, Rural Housing Departments/wings, Housing Boards, Electricity Boards, Urban Development Authorities etc. The Head of the District shall identify the agency through which a particular work recommended by the MP should be executed.

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे । टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर दिया गया है । इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाना चाहिए । इन निधियों का उपयोग सेवा संबंधी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है । फिर भी इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख–रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय शामिल नहीं किया जाएगा।

2.3 यह भी उचित होगा कि इस योजना से संबंधित निधियों का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रुप से पूरा करने के लिए किया जाए, उदाहरण के लिए तटबंध और उसमें जल निकास करने संबंधी किसी छोटे कार्य (माइक्रो–हाइडेल वर्क) की लागत आंशिक रुप से पूरा करने का कार्य केवल उसी स्थिति में किया जाए जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस पैरा के अधीन जहां किसी परियोजना का अंशतः खर्च इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रुप से पहचान के योग्य हो।

2.4 कभी–कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनके निष्पादन में एक वर्ष से ज्यादा समय लग सकता है । इन परिस्थितियों में इस योजना के अंतर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रुप से ध्यान में रखते हुए निधि अग्रिम रुप से अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

2.5 सांसद द्वारा चुने गए कार्य के स्थल को सांसद की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है ।

2.6 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों को स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जो आम जनता के लिए पूर्णतः उपलब्ध होंगे । ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास निहित होगा । सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निर्मित परिसंपत्तियों का विक्रय/हस्तांतरण/व्ययन सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। इन निर्मित परिसंपत्तियों का रख–रखाव एवं व्यवस्था लाभार्थी संगठनों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी एवं सरकार उनकी आवधिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण करेगी । सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत दी गई कार्यनीति के अनुसार अनुमेय स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए एम पी लैड्स निधियों का उपयोग करने से पूर्व सरकार के अतिरिक्त अन्य लाभार्थी संगठन को उपरोक्त शर्त का अनुपालन करने हेतु सरकार के साथ औपचारिक करार पर अग्रिम रुप से हस्ताक्षर करने होंगे।

2.7 इस योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची परिशिष्ट–1 मे दी गई है । इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है, उसकी सूची परिशिष्ट–2 में दी गई है ।

2.8 इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है।

2.9 जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संबद्ध अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं, पंजीकृत संगठन इत्यादि।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन :

3.1 निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने और उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के पहले जिलाधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित सांसद की सहमति प्राप्त करें । सामान्यतः सांसदों की सलाह अभिभावी होनी चाहिए, यदि निर्माण कार्यों को करवाए जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो । जिन मामलों में जिलाधिकारी यह समझते हैं कि सांसद द्वारा सुझाया गया कार्य निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके संबंध में उन्हें कारणों सहित एक व्यापक

2.2 The works under the scheme shall be developmental in nature based on locally felt needs. The emphasis is on creation of durable assets. Funds provided under the scheme should not be used for incurring revenue expenditure. The funds can also be used for purposes such as provision of service support facilities. However, they will not include any recurring expenditure like on staff to maintain such facilities.

2.3 It will also be appropriate if the scheme funds are used for partly meeting the cost of a larger work like for example for partly meeting the cost of a micro-hydel work only in case it would result in completion of the works. Where such part costs are met under this para, it should be with reference to clearly identifiable part of the work.

2.4 Sometimes execution of work, by their very nature, may span into more than one year. In such circumstances, funds under the scheme could be made available to the executing agency either in advance or over more than one year, phasing of execution of work being clearly kept in view.

2.5 The site selected for execution of the work by the MP shall not be changed except with the concurrence of the MP himself.

2.6 The funds under MPLADS may be used for creation of durable assets which shall always be available for public use at large. The ownership of such assets created with MPLADS funds would vest in the Government. The sale/transfer/disposal of the assets created out of MPLADS funds shall not be undertaken without the prior approval of the Government. The maintenance and upkeep of assets so created will have to be ensured by the beneficiary organisation and will be subject to periodical audit and inspection by the Government. Beneficiary organisations other than Government must enter into a formal agreement, in advance, with Government to comply with the above conditions before the funds from MPLADS are used for creation of a durable assets permissible as per procedure laid down under the MPLADS guidelines.

2.7 An illustrative list of works that may be taken up under the scheme is presented in Appendix 1. A list of works which shall not be allowed under the scheme is presented in Appendix 2.

2.8 Payment of advances of any type to the contractors/suppliers under any work falling within this scheme is prohibited.

2.9 The Heads of Districts should ensure that provision for maintenance and upkeep of the works to be taken up under this Scheme is forthcoming from the concerned local body or the relevant agency, that is, Government-aided institution, registered society etc.

SANCTION AND EXECUTION OF WORKS

3.1 In identifying and selecting works and giving administrative sanction for the same, the Head of the District should invariably get the concurrence of the Member of Parliament. Normally, the advice of the MP should prevail unless it be for technical reasons such as land selected for work not being suitable for execution etc. Where the Head of the District considers that a work suggested by an MP cannot be executed, he should send a comprehensive report

रिपोर्ट राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित करते हुए, सम्बद्ध सांसद को भेजना चाहिए ।

3.2 जहां तक संभव हो, सभी निर्माण कार्यों को संबंधित संसद सदस्य से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए ।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरियों का संबंध है, इस संबंध में निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण एवं अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देनी चाहिए ।

3.4 एक से अधिक जिलों में फैले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह जिलाधिकारी जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि को प्राप्त करते हैं, संसद सदस्य की इच्छानुसार अपेक्षित धनराशि अन्य संबंधित जिलों को भी उपलब्ध करवांएगे ताकि अन्य जिलों के सांसदों द्वारा उनके जिले/जिलों में सुझाए गए निर्माण कार्यों को कार्यान्वित कर सकें।

3.5 चूंकि इस योजना के तहत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और मलव्ययन बोर्ड, आवास निगम आदि जैसे राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाएगा, अतः संबंधित जिलाधिकारी इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों के समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे । उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण आरंभिक कार्यों, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक खर्च, सेंटेज आदि नहीं लेंगे।

3.6 इस योजना के लिए केंद्र में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रक जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार के संबंधित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को यह सामान्य निर्देश जारी करेंगे कि वे जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत उन्हें अग्रेषित किए गए निर्माण कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित कराएं । ऐसे निर्देशों की प्रतियां संसद सदस्यों को भी निर्वाचन क्षेत्रों तथा दिल्ली में स्थित उनके पतों पर भेजी जाएं।

3.7 इस योजना के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियों पर सामान्य वित्तीय और लेखा–परीक्षण संबंधी प्रक्रियाएं इन दिशा निर्देशों, खासकर पैरा 3.3 में निहित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लागू होंगी ।

3.8 इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष का आबंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है । हालांकि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य बदल सकते हैं, चाहे ऐसे बदलाव के कारण कुछ भी हों, चूंकि आबंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए । जिलाधिकारी इस संबंध में पूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभाएंगे।

3.9 जब कभी संसद सदस्य बदलेंगे, चाहे इसके कारण कुछ भी हों, कार्यों के क्रियान्वयन में यथासंभव निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे :

*यदि पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे पूरा किया जाएगा ।

*यदि पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लंबित पड़ा हो तो उसे भी निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि वह अन्यथा मानदंडों के अनुरुप हो ।

with reasons to the MP under intimation to the Department of the State Government dealing with the subject and to the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

3.2 As far as possible, all sanctions for works should be accorded within 45 days from the date of receipt of proposal from the concerned MP.

3.3 So far as technical and administrative sanctions are concerned, decision making should be only at the District level. If need be for the purpose of implementation of this scheme, full and final powers should be delegated to the District technical and administrative functionaries.

3.4 In case, a constituency fall in more than one District, the Head of the District who receives the money released by the Government of India shall make the required funds available to the other concerned District(s) in keeping with MP's choice so that the Head(s) of such other District(s) could implement the works suggested by the MP in his District(s).

3.5 Since the works under this scheme would be implemented by different State Government agencies such as PWD, Rural Development, Irrigation, Agriculture, Health, Education, Area Development Authorities, Water Supply and Sewerage Boards, Housing Corporation etc. the Heads of the respective Districts would be responsible for the coordination and overall supervision of the works under this scheme at the District level. The implementing agencies may not collect any administrative charges, centage etc. for their services of preparatory work, implementation, supervision, etc.

3.6 The Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, would have the nodal responsibilities for this scheme at the Centre. The Department concerned of the State Government will issue general instructions to all the planning and implementing agencies at the District level to co-operate, assist and implement the works referred to them under this scheme by the Heads of the Districts. Copies of such instructions shall also be sent to the MPs at their constituencies and at their Delhi addresses.

3.7 The normal financial and audit procedures would apply to all actions taken under this scheme subject to these Guidelines, especially Guidelines contained in para 3.3.

3.8 Allocation per year under the scheme is for the constituency. Though there may be change in the MP representing a constituency, whatever may be the reason for such change, the allocation being for the constituency, continuity of action in implementing works under the scheme should be maintained. The Head of the District should play a coordinating role in this regard between the past and the present MP and the implementing agencies concerned.

3.9 When there is a change in the MP, for whatever reason it may be, the following principles should be followed, as far as possible in executing works:

* If the work identified by the predecessor MP is under execution, it should be completed.

* If the work identified by the predecessor MP is pending sanction due to administrative reasons beyond a period of 45 days from the date on which advice was received for taking up the work, it should also be executed provided the work is otherwise as per norms.

*यदि पूर्ववर्ती सांसद किसी कार्य को अभिज्ञापित कर चुके हों परंतु इसके पहले कि उप पैरा में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरु नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती संसद सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे ।

3.10 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एक राज्य विशेष में राज्य सभा के पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा छोड़ी गई अप्रयुक्त शेष राशि उस राज्य विशेष के उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दी जाएगी । राज्य सभा/लोक सभा के पूर्ववर्ती मनोनीत सदस्यों द्वारा छोड़ी गई अप्रयुक्त शेष राशि राज्य सभा/लोक सभा के उत्तरवर्ती मनोनीत सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दी जाएगी ।

धनराशि का अवमोचन

4.1 यद्यपि संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 25 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों का सुझाव नहीं देंगे तथापि, प्रति कार्य 25 लाख रुपये की लागत सीमा का बहुत सख्ती से अनुपालन किया जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए । किसी एक कार्य के लिए 25 लाख रुपये से अधिक की लागत राशि, कार्य के स्वरुप को देखते हुए खर्च की जा सकती है । उदाहरण के लिए लघु सिंचाई योजना या जल आपूर्ति के लिए सिंगल चेक बांध अथवा खेलकूद स्टेडियम बनवाने में 25 लाख रुपये से अधिक की लागत आ सकती है । ऐसे निर्माण कार्यों में अधिक राशि खर्च की जा सकती है ।

4.2 धनराशि हर वर्ष लेखानुदान/बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को अवमुक्त कर दी जाएगी । इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि व्यपगत नहीं होगी । यदि किसी एक वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो वह अगले वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी तथा प्रति निर्वाचन क्षेत्र प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए के आबंटन में कोई कमी नहीं की जाएगी । तथापि, निधियों का अवमोचन किए गए वास्तविक व्यय और कार्य निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में बजट में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए तक की निधियां उपलब्ध रहेंगी तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे । इसके साथ निधियों का अवमोचन प्रगति के अनुसार किया जाएगा । इसका अर्थ यह है कि किसी भी समय एक वर्ष की अवधि में जितनी धनराशि का व्यय अपेक्षित हो सकता है उससे अत्यधिक राशि सरकारी खजाने से बाहर पड़ी न रहे । उदाहरण के लिए यदि किसी एक वर्ष में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित दो करोड़ रुपए में से केवल 150 लाख रुपए खर्च होते हैं तो बाकि 50 लाख रुपए अगले वर्ष के लिए माने जाएंगे और तब उस वर्ष के दो करोड़ रुपए के आबंटन समेत (2.5 करोड़ रुपए) यह राशि अगले वर्ष की हकदारी हो जाएगी और वह खर्च की जा सकती है । परंतु निधियों का वास्तविक अवमोचन खर्च के लिए अपेक्षित राशि को देखते हुए ही किया जायेगा । तथापि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बकाया अधिशेष राशि बहुत बड़ी हकदारी के रुप में इकट्ठी न हो जाए ।

4.3 निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए धनराशि को आगामी आवश्यकता के आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निधियां वर्ष में दो बार जारी की जाएंगी ।

4.4 निधियां जारी करते समय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित जिलाधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करेगा । धनराशि की ऐसी आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए बाकी आबंटन पर विचार किया जायेगा । सांसद के लिए एक करोड़ रु0 की किश्त सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि (अस्वीकृत शेष) 50 लाख रु0 से कम होने पर जारी की जाएगी । किश्त जारी करने के लिए सांसद की योग्यता, संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा परिशिष्ट क्रमशः 3 और 4 पर रखे गए प्रपत्र में प्रेषित सूचना के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिलाध्यक्षों द्वारा संबंधित सांसदों को भी भेजी जाएंगी ।

* If the predecessor MP had identified the work, but it was not taken up for execution because of reasons other than those mentioned in the preceding sub-para, it can be executed subject to the confirmation of the successor MP.

3.10 In respect of elected Members of Rajya Sabha, the unspent balance left by the predecessor Members of Rajya Sabha in a particular State will be equally distributed among the successor Rajya Sabha Members in that particular State.

The unspent balance left by the predecessor Nominated Members of Rajya Sabha/Lok Sabha will be equally distributed amongst the successor Nominated Members of Rajya Sabha/Lok Sabha respectively.

RELEASE OF FUNDS

4.1 Ideally it would be desirable that the MPs suggest individual works costing not more than Rs. 25 lakhs per work. However, the limit of Rs. 25 lakhs per work should not be too rigidly construed. Amounts higher than Rs. 25 lakhs per work can be spent depending upon the nature of the work. (For example a single check dam to provide minor irrigation or water supply or a sports stadium may cost more than Rs. 25 lakhs. In the case of such works higher amount can be legitimately spent).

4.2 Funds shall be released to the Districts each year immediately after the Vote on Account/Budget is passed. The funds released by the Govt. of India under the scheme would be non-lapsable. Funds released in a particular year, if they remain unutilised can be carried forward to the subsequent year without detracting from the allocation of rupees two crores per year per constituency. However, release of funds will be made with reference to the actual progress achieved in expenditure and execution of works. In other words, funds would be available in the budget to the extent of rupees two crores per year per MP and works will not suffer for want of provisions. At the same time releases will be regulated according to progress. The idea is that at any given time no excessive money should remain outside the Government treasury than is reasonably expected to be spent within a year. For example, if out of Rs. 2 crore allotted for a constituency in a year, Rs. 150 lakhs are spent, the balance of Rs. 50 lakhs can be carried over for the year when this amount together with fresh allocation of Rs. 2 crore (total of Rs. 2.5 crore) would be the entitlement of the year and could be spent. But actual physical release of funds will be with reference to the amount expected to be spent. It should be seen, however, that unspent amounts do not excessively snowball into huge entitlements.

4.3 The release of funds by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, will be done two times a year on the basis of the physical and financial progress of the works under implementation and further requirement of funds for works.

4.4 At the time of release of funds, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, in consultation with the Heads of the concerned Districts will make an assessment of the funds required to complete the on-going works. Such requirements of funds will be met first and then only the balance allocation will be considered for new works. Instalment of Rs. 1 crore in respect of an MP would be released once the balance amount, after taking into account the cost of all the works sanctioned (unsanctioned balance), comes to less than Rs. 50 lakhs. The eligibility for the release of an instalment in respect of an MP will be decided on the basis of information furnished by the concerned District Heads in the format placed at Appendix-3 and 4 respectively, copies of which will also be sent by the District Heads to the concerned MPs.

4.5 किसी एक कार्य के लिए निधियों को तत्परता के साथ जारी किया जाना चाहिए । निर्माणाधीन कार्यों की लागत का 75 प्रतिशत पहली किश्त के रुप में और बकाया 25 प्रतिशत कार्य की प्रगति को देखकर जारी किया जाएगा । जहां तक संभव हो कार्य स्थल के सबसे नजदीक उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि प्रखण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निधियां अवमुक्त की जानी चाहिए । इसका प्रयोजन यह है कि निधियों का अवमोचन भी कार्यस्थल पर पहले से उपलब्ध विकेंद्रित प्रशासनिक तंत्र के जरिए किया जाए तथा वह कार्यान्वित करने वाला अभिकरण उन विकेंद्रित प्राधिकारों से शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करने की स्थिति में हो ।

4.6 यदि संबंधित सांसद निधियों का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं तो उसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को लिखना चाहिए ताकि निधियों का निर्गम वापस लिया जा सके ।

4.7 योजना के अंतर्गत जारी निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जाएगा ।

4.8 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज को दिशा निर्देशों के अधीन अनुमोदित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

प्रबोधन व्यवस्था

5.1 इस योजना के अंतर्गत शुरु किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, क्षेत्रीय निरीक्षण के द्वारा वास्तविक प्रबोधन तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ समन्वय बनाये रखने के लिए एक केंद्रक विभाग को नामित करेंगे । जिलाधीश को दौरा कर इन कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रुप से इन निर्माण कार्य स्थलों का दौरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टयों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है । इसी तरह उप-क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्य के स्थलों को दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट प्रबोधन करना चाहिए । जिलाधीश को चाहिए कि वे ऐसे निरीक्षणों तथा प्रबोधन में, जहां तक संभव हो, संसद सदस्यों को भी शामिल करें । उन्हें संसद सदस्यों और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दो महीने में एक बार उपर्युक्त प्रबोधन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए । सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें निष्पादन अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों की कम से कम संख्या निर्धारित हों ।

5.2 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं नवीनतम स्थिति की जानकारी हमेशा रखेगा ।

5.3 इस योजना से संबंधित प्रबोधन प्रपत्र तथा अन्य मुद्दे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा योजना के ढांचे के अंतर्गत समय-समय पर तय किए जाएंगे ।

5.4 जिलाधीशों को चाहिए कि वे इस योजना के अंतर्गत कार्यों की प्रगति के संबंध में सूचना इंटरनेट के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भी दें । इस रिपोर्ट की प्रतियां सांसदों को भी भेजी जाएं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इंटरनेट पर रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगा । इससे निर्वाचन क्षेत्र-वार योजना की प्रगति के तत्काल प्रबोधन की सुविधा भी हो जाएगी ।

4.5 Funds for individual works should be promptly released. 75% of the cost of the works can be released in the first instalment itself, the balance of 25% being released watching progress. To the maximum extent possible, release of funds should be arranged through the administrative authority available nearest to the work spot, like for example a Block Development Officer. The objective should be that release of funds also is made through decentralised administrative mechanisms already available on the ground and that implementing agencies have the quickest feasible access to such decentralised authorities.

4.6 In case the concerned MP is not interested in utilising the funds, he may write to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, so that the release of funds is withdrawn.

4.7 Funds released under the scheme shall be deposited in nationalized banks.

4.8 Interest accrued on the funds deposited in nationalized banks may be used for the works approved under these guidelines.

MONITORING ARRANGEMENTS

5.1 For effective implementation of the works taken up under this scheme, each State Government/UT Administration shall designate one nodal Department for physical monitoring through field inspection and for coordination with the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. The Heads of Districts shall visit and inspect at least 10% of these works every year. Similarly, it should be the responsibility of the senior officers of implementing agencies of these works to regularly visit the work spots and ensure that the works are progressing satisfactorily as per the prescribed procedures and specifications. Likewise, officers of District at the sub-divisional and block level shall also closely monitor implementation of these works through visits to work sites. The Head of the District should also involve the MPs in such inspections and monitoring to the maximum extent feasible. They should also furnish monitoring reports once in two months to the MPs and the Ministry of Statistics and Programme Implementation. A schedule of inspections which prescribes the minimum number of field visits for each supervisory level functionary of the implementing agencies may be drawn up by the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

5.2 The Ministry of Statistics and Programme Implementation, would always have with it a complete and updated picture of the works under implementation.

5.3 Monitoring formats and other issues of details relevant to this scheme would be decided by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, from time to time within the framework of the scheme.

5.4 The Districts Heads should also communicate information on the progress of works under the scheme on the Internet to the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Copies of such reports shall also be forwarded to the MPs. Software required for reporting on the Internet will be furnished by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. This will also facilitate instantaneous monitoring of the progress of the scheme constituency-wise.

5.5 योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने हेतु मुख्य सचिव या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा जिलाध्यक्षों और संसद सदस्यों को शामिल करते हुए वर्ष में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए ।

5.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं और विशेषज्ञों का लाभ उठाते हुए दूरभाष कांफ्रेंस भी आयोजित की जा सकती है । सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित ऐसी कांफ्रेंस में जिलों के प्रधान तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों से तत्काल संपर्क किया जा सकेगा जिससे कि शंकाओं को दूर करने तथा अवरोधों को हटाने में मदद मिलेगी ।

5.7 संबंधित राज्य सरकारें, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जिला पदधारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं । जिला पदधारियों के प्रकार्यों तथा निष्पादन में प्राप्त अनुभवों के आलोक में, योजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपचारी उपायों को शामिल किया जाए।

सामान्य

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष, संसद सदस्य द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों से करवाये गये हैं, "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का निर्माण कार्य", सांसद के नाम के साथ अंकित सूचना फलक कार्य स्थलों पर स्थाई तौर पर और प्रमुख रुप से लगाए जाएं ।

6.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान संसद सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी संभावना एवं उल्लेख इन दिशा निर्देशों में नहीं है । समुचित स्पष्टीकरण के लिए ऐसे मामले सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष रखे जा सकते हैं ।

6.3 इन दिशा निर्देशों में अनुमेय कार्यों को उन पंजीकृत समितियों एवं न्यासों के लिए भी किया जा सकता है, जो परिशिष्ट–5 पर प्रस्तुत इस मंत्रालय के पत्र सं0 सी/56/2000–एमपीलैड्स, दिनांक 23.01.2001 तथा पत्र सं0 सी/56/2000–एमपीलैड्स, दिनांक 20.03.2001 में दी गई शर्तों का अनुपालन करते हों ।

6.4 परिशिष्ट–6 में दिए गए इस मंत्रालय के पत्र सं0 सी /50/2000–एमपीलैड्स, दिनांक 22.01.2001 द्वारा संप्रेषित ब्यौरे के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियां संबंधित सांसदों की अनुशंसा पर, उनके निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना में राज्य सरकार के योगदान के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है ।

5.5 The Chief Secretary or in his absence a Senior Principal Secretary/Additional Chief Secretary should conduct a meeting involving the Heads of Districts and MPs to assess the progress of works under the scheme at least once in a year.

5.6 Periodic teleconferences may also be organised, availing of the infrastructure and expertise available with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and the Indian Space Research Organisation (ISRO). In these conferences to be organised by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, instantaneous contact could be established with the Heads of Districts and other local functionaries to clarify doubts and remove bottlenecks. MPs also should be associated with such conferences.

5.7 State Governments concerned may make arrangements for training of District officials concerned with the implementation of MPLAD Scheme. In the light of experience gained in the functioning and performance of District officials, corrective measures may be incorporated by the States in their training programmes to improve deficiencies observed in implementation of the Scheme.

GENERAL

6.1 In order that local people become aware that particular works have been executed with MPLADS funds, signboards carrying the inscription "MPLADS WORK" with the name of MP may be permanently and prominently erected at the sites.

6.2 In execution of works, MPs may face special problems/situations not envisaged and covered under these guidelines. Such cases may be taken up with the Ministry of Statistics and Programme Implementation, for suitable clarification.

6.3 Works permissible under these Guidelines may also be taken up for certain Registered Societies and Trusts, who fulfill the conditions laid down in Ministry's letter No. C/56/2000-MPLADS dated 23.01.2001 and letter No. C/56/2000-MPLADS dated 20.03.2001 placed at Appendix-5.

6.4 MPLADS funds can also be used on the recommendation of the MPs concerned towards contribution of State Government in Centrally Sponsored Scheme, in their constituency as per details communicated under this Ministry's letter No. C/50/2000-MPLADS dated 22.01.2001 at Appendix-6.

परिशिष्ट--1

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की व्याख्यात्मक सूची

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों । ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परंतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है बशर्ते संस्थान दो साल से कार्य कर रहे हों ।

2. गांवों, शहरों तथा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के वास्ते नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हों । पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी के टैंकर भी क्रय किये जा सकते हैं ।

3. गांवों, शहरों तथा नगरों में सड़कों का निर्माण जिसमें पार्ट-सड़कें, संपर्क सड़कें, लिंक सड़कें आदि भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की जा रही जरूरतों को पूरा करने के लिए संबद्ध संसद सदस्य और जिला प्रधान की सहमति से अत्यन्त कुनिंदा कच्चे मार्गों का भी निर्माण करवाया जा सकता है।

4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों अथवा नलकूपों की नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण ।

5. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण ।

6. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण । व्यायाम केंद्रों, खेल-कूद संघों, शारीरिक शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों आदि में बहुव्यायाम (मल्टीजिम) सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति है ।

7. सरकारी तथा सामुदायिक भूमियों अथवा अन्य प्रदत्त भूखण्डों पर सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, बागबानी, चरागाहों, पार्कों एवं उद्यानों की व्यवस्था ।

8. गांवों, कस्बों और शहरों में तालाबों की सफाई करवाना ।

9. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण ।

10. सामुदायिक उपयोग एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए गोबर गैस संयंत्रों, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/साधन उपयोगों का निर्माण ।

11. सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल रीचार्जिंग सुविधाओं का निर्माण ।

12. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण ।

13. शिशु गृहों एवं आंगनवाड़ियों का निर्माण ।

14. ए एन एम आवासीय मकानों के साथ-साथ परिवार कल्याण उपकेंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी भवनों का निर्माण। सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए भी ऐसे भवनों का निर्माण किया जा सकता है ।

15. शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और छांवों का निर्माण ।

16. सार्वजनिक शौचालयों और स्नान-गृहों का निर्माण ।

17. नाले और गटरों का निर्माण ।

18. पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण ।

APPENDIX-1

ILLUSTRATIVE LIST OF WORKS THAT CAN BE TAKEN UP UNDER MPLADS

1. Construction of buildings for schools, hostels, libraries and other buildings of educational institutions belonging to Government or local bodies. Such buildings belonging to aided institutions and unaided but recognised institutions can also be constructed provided, however, that the institution be in existence for not less than two years.

2. Construction of tube-wells and water tanks for providing water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works, which may help in this respect. Water tankers can also be purchased for providing drinking water.

3. Construction of roads including part roads, approach roads, link roads etc. in villages and towns and cities. Very selectively kutcha roads can also be constructed where the MP concerned and the District Head agree to meet the locally felt need.

4. Construction of culverts/bridges on the roads of above description and of open cut or tube wells.

5. Construction of common shelters for the old or handicapped.

6. Construction of buildings for local bodies for recognised District or State Sports Associations and for cultural and sports activities or for hospitals. Provision of multi-gym facilities in gymnastic centres, sports associations, physical education training institutions etc. is also permissible.

7. Special forestry, farm forestry, horticulture, pastures, parks and gardens in Government and community lands or other surrendered lands.

8. Desilting of ponds in villages, towns and cities.

9. Construction of public irrigation and public drainage facilities.

10. Construction of common gobar gas plants, non-conventional energy systems/devices for community use and related activities.

11. Construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities.

12. Construction of public libraries and reading rooms.

13. Construction of creches and anganwadis.

14. Construction of public health care buildings, including family welfare sub-centres together with the ANM residential quarters. Such buildings belonging to aided institutions also can be constructed.

15. Construction of crematoriums and structures on burial/cremation grounds.

16. Construction of public toilets and bathrooms.

17. Construction of drains and gutters.

18. Construction of footpaths, pathways and footbridges.

19. शहरों, कस्बों तथा गांवों की गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था । गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला शेडों का प्रावधान ।

20. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण ।

21. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस पड़ाव/शेडों का निर्माण ।

22. पशु चिकित्सा सहायता केंद्रो, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों और प्रजनन केंद्रों का निर्माण ।

23. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स–रे मशीन, ऐम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपस्करों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना । ऐम्बुलेंस की सुविधाएं, रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं को प्रदान की जा सकती हैं ।

24. इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनाएं:–

    1. हाई स्कूल/कॉलेज की शिक्षण परियोजना में कंप्यूटर ।

    2. सूचना फुटपाथ ।

    3. उच्च विद्यालयों में हैम क्लब ।

    4. सिटीजन बैंड रेडियो ।

    5. ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना ।

25. कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंग पर लैवल क्रासिंग का निर्माण ।

26. सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य–दृश्य साधनों का क्रय, बशर्ते इन की सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्रावधान हो ।

27. स्थानीय निकायों के लिए नाइट स्वायल डिस्पोजल प्रणाली का क्रय ।

28. बाढ़ एवं तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोटर बोटों का क्रय।

29. पशुओं की देखभाल/कल्याण संबंधी कार्य जैसे भवनों/आश्रय स्थलों का निर्माण, एंबुलैंस, चिकित्सा उपकरण का प्रावधान और आधारभूत सुविधाओं का विकास जैसे पेयजल, जल निकास इत्यादि का प्रावधान;

19. Provision of civic amenities like electricity, water, pathways, public toilets etc. in slum areas of cities, town and villages and in SC/ST habitations, provision of common work-sheds in slums and for artisans.

20. Construction of residential schools in tribal areas.

21. Construction of bus-sheds/stops for public transport passengers.

22. Construction of veterinary aid centres, artificial insemination centres and breeding centres.

23. Procurement of hospital equipment like X-Ray machines, ambulances for Government Hospitals and setting up of mobile dispensaries in rural areas by Government Panchayati Institutions. Ambulances can be provided to reputed service organisations like Red Cross, Ramakrishna Mission etc.

24. Electronic Projects:

    i) Computer in education project of High school/College

    ii) Information footpath

    iii) Ham Club in high schools

    iv) Citizen band radio

    v) Bibliographic data-base projects.

25. Construction of Level Crossing at unmanned Railway crossing.

26. Purchase of Audio-Visual Aids of educational nature for Government, Government-aided and also unaided but Government recognised educational institutions provided there is proper place and proper provision for safe custody of these aids.

27. Purchase of Night Soil Disposal System for local bodies.

28. Purchase of motor boats for flood and cyclone affected areas.

29. "Works relating to animal care/welfare like construction of buildings/shelters, provision of ambulances, medical equipment and development of infrastructure facilities like provision of drinking water, drainage etc."

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत न कराए जा सकने वाले कार्यों की सूची ।

1. केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संस्थाओं से संबंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण ।
2. वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य ।
3. किसी भी स्थायी परिसंपत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य ।
4. अनुदान और ऋण ।
5. स्मारक या स्मारक भवन ।
6. किसी भी प्रकार की वस्तु/सामान की खरीद अथवा भण्डार ।
7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिगृहित भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि ।
8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्ति, उन परिसंपत्तियों को छोड़कर, जो अनुमोदित योजनाओं के भाग हैं।
9. धार्मिक–पूजा स्थल ।

APPENDIX–2

LIST OF WORKS NOT PERMISSIBLE UNDER MPLADS

1. Office buildings, residential buildings, and other buildings relating to Central or State Governments, Departments, Agencies or Organisations.
2. Works belonging to commercial organisations, private institutions or co-operative institutions.
3. Repair and maintenance works of any type other than special repairs for restoration/up-gradation of any durable asset.
4. Grant and loans.
5. Memorials or memorial buildings.
6. Purchase of inventory or stock of any type.
7. Acquisition of land or any compensation for land acquired.
8. Assets for all individual benefit, except those which are part of approved schemes.
9. Places for religious worship.

परिशिष्ट–3

लोकसभा के संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निधियों के अवमोचन [illegible] व्यय की सूचना हेतु प्रारूप

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सूचना विवरण (दिनांक .... तक)

राज्य का नाम :		
निर्वाचन क्षेत्र का नाम :		
सांसद का नाम :		
10वीं लोकसभा		
11वीं लोकसभा		
12वीं लोकसभा		
13वीं लोकसभा		
केन्द्रक जिले का नाम :		
पता :		
फोन नं0 एसटीडी कोड के साथ :		
फैक्स :	ई–मेल	
1. निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त कुल निधियां		प्राप्त निधियां
		(रु0 लाखों में)
(क) भारत सरकार से प्राप्त निधियां	वर्ष	
	1993–94	
	1994–95	
	1995–96	
	1996–97	
	1997–98	
	1998–99	
	1999–2000	
	2000–2001	
	2001–2002	
	2002–2003	
	कुल	
(ख) निधियों पर अर्जित ब्याज की कुल राशि		
(ग) कुल (क+ख)		

APPENDIX-3

FORMAT FOR INFORMATION ON RELEASE OF FUNDS, WORKS SANCTIONED AND EXPENDITURE UNDER MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS) FOR LOK SABHA MPs

STATEMENT OF INFORMATION UNDER MPLADS (UP TO DATE):

NAME OF THE STATE:		
NAME OF THE CONSTITUENCY:		
NAME OF THE MP:		
10th LS:		
11th LS:		
12th LS:		
13th LS:		
NAME OF THE NODAL DISTRICT:		
ADDRESS:		
PHONE NO. WITH STD CODE:		
FAX:: e-mail		
I Total funds received for the constituency:		FUNDS RECEIVED
		(Rs. In Lakhs)
(a) Funds received from the Govt. of India	YEAR	
	1993-94	
	1994-95	
	1995-96	
	1996-97	
	1997-98	
	1998-99	
	1999-2000	
	2000-2001	
	2001-2002	
	2002-2003	
	TOTAL	
(b) Total amount of interest accrued on the funds		
(c) TOTAL (a+b)		

2. अनुशंसित कार्यों की लागत एवं कुल सं.	कार्यों की सं.	अनुमानित लागत
(क) 10वीं लोकसभा के सांसद द्वारा		
(ख) 11वीं लोकसभा के सांसद द्वारा		
(ग) 12वीं लोकसभा के सांसद द्वारा		
(घ) 13वीं लोकसभा के सांसद द्वारा		
(ङ) कुल (क+ख+ग+घ)		
3. निम्न की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्यों की लागत एवं सं.	कार्यों की सं.	स्वीकृत राशि
(क) 10वीं लोकसभा के सांसद		
(ख) 11वीं लोकसभा के सांसद		
(ग) 12वीं लोकसभा के सांसद		
(घ) 13वीं लोकसभा के सांसद		
(ङ) कुल (क+ख+ग+घ)		
4. निर्वाचन क्षेत्र के पास उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष 1 (ग) – 3 (ङ)		
5. निर्वाचन क्षेत्र में पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या		
6. शुरु किए गए पर अधूरे कार्यों की कुल संख्या		
7. कुल वास्तविक व्यय		

दिनांक: जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/नगर निगम के मु0का0अधि0 के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : श्री/श्रीमती.....संसद सदस्य ।

नोट: (1) 100 लाख रुपए की अगली देय किश्त तभी जारी की जाएगी जब कॉलम 4 में दी गई राशि 50 लाख रुपए से कम होगी ।

(2) केंद्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना भी हो जो कि उन निर्वाचन क्षेत्र में आते हों, जहां सांसद की अनुशंसा पर निधियां स्थानांतरित की गई ।

(3) स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए योजना एवं प्राक्कलन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन मिला है, को कॉलम सं. 3 में स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिए ।

2 Total No. and cost of works recommended:	No. of works	Estimated cost
(a) By the 10th LS MP		
(b) By the 11th LS MP		
(c) By the 12th LS MP		
(d) By the 13th LS MP		
(e) TOTAL (a+b+c+d)		
3 No. and cost of works sanctioned on recommendations of:	No. of works	Amount sanctioned
(a) The 10th LS MP		
(b) The 11th LS MP		
(c) The 12th LS MP		
(d) The 13th LS MP		
(e) TOTAL (a+b+c+d)		
4 Total unsanctioned balance available with the constituency 1(c)-3(e)		
5 Total No. of works completed in the constituency		
6 Total No. of works started but not completed		
7 Total actual expenditure		

Date:

Signature of the Distt. Collector/Distt. Magistrate/Dy. Commissioner/
CEO of Municipal Corporation

Copy to:

Shri/Smt._____.

Member of Parliament

Note:

(i) The next due instalment of Rs. 1 crore is released only when the amount in respect of column No. 4 is reported as less than Rs. 50 lakhs.

(ii) The Nodal District Collector is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.

(iii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued after finalising plans & estimates. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported as sanctioned in column No. 3

राज्य सभा के संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निधियों के अवमोचन स्वीकृत कार्य तथा व्यय की सूचना हेतु प्रारुप

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सूचना विवरण (दिनांक.....तक)

राज्य का नाम		
राज्यसभा के सांसद का नाम :		
केन्द्रक जिले का नाम :		
पता :		
फोन नं0 एस.टी.डी. कोड के साथ :		
फैक्स : ई–मेल		
1. राज्यसभा सांसद के लिए प्राप्त कुल निधि	वर्ष	प्राप्त निधियां
		(लाखों रु0 में)
(क) भारत सरकार से प्राप्त निधियां	1993–94	
	1994–95	
	1995–96	
	1996–97	
	1997–98	
	1998–99	
	1999–2000.	
	2000–2001	
	2001–2002	
	2002–2003	
	योग	
(ख) निधियों पर अर्जित ब्याज की कुल राशि		
(ग) सांसद के लिए प्राप्त पूर्ववर्ती सांसद का अव्ययित शेष		
(घ) योग (क+ख+ग)		
2. अनुसंशित कुल कार्यों की संख्या तथा लागत	कार्यों की सं0	अनुमानित लागत
3. स्वीकृत कुल कार्यों की संख्या तथा लागत	कार्यों की सं0	स्वीकृत धनराशि
4. सांसद के संबंध में उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष–1 (ग)–3		
5. सांसद के संबंध में पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या		
6. शुरु किए गए पर अधूरे कार्यों की कुल संख्या		
7. कुल वास्तविक व्यय		

दिनांक: जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/नगर निगम के मु0का0अधि0 के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : श्री/श्रीमती.....संसद सदस्य ।

नोट: (1) 100 लाख रुपए की अगली देय किश्त तभी जारी की जाएगी जब कॉलम 4 में दी गई राशि 50 लाख रुपए से कम होगी ।

(2) केंद्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना भी हो जो कि निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं जहां सांसद की अनुशंसा पर निधियां स्थानांतरित की गई ।

(3) स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए योजना एवं प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन मिला है, को कॉलम सं. 3 में स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिए ।

APPENDIX-4

FORMAT FOR INFORMATION ON RELEASE OF FUNDS, WORKS SANCTIONED AND EXPENDITURE UNDER MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS) FOR RAJYA SABHA MPs

STATEMENT OF INFOR`MATION UNDER MPLADS (UP TO DATE:)

NAME OF THE STATE:		
NAME OF THE RS MP:		
NAME OF THE NODAL DISTRICT:		
ADDRESS:		
PHONE NO. WITH STD CODE:		
FAX:		
e-mail		
1. Total funds received for the RS MP		FUNDS RECEIVED
(a) Funds received from the Govt. of India	YEAR	(Rs. In Lakhs)
	1993-94	
	1994-95	
	1995-96	
	1996-97	
	1997-98	
	1998-99	
	1999-2000	
	2000-2001	
	2001-2002	
	2002-2003	
	TOTAL	
(b) Total amount of interest accrued on the funds		
(c) Unspent balance of predecessor MPs received for the MP		
(d) TOTAL (a+b+c)		
2 Total No. and cost of works recommended	No. of works	Estimated cost
3 Total No. and cost of works sanctioned	No. of works	Amount sanctioned
4 Total unsanctioned balance available in respect of the MP 1(c)-3		
5 Total No. of works completed in respect of the MP		
6 Total No. of works started but not completed		
7 Total actual expenditure		

Date:

Copy to:

Signature of the Distt. Collector/Distt. Magistrate/Dy. Commissioner
CEO of Municipal Corporation

Shri/Smt._____. Member of Parliament

Note:

(i) The next due instalment of Rs. 1 crore is released only when the amount in respect of column No. 4 is reported as less than Rs. 50 lakhs.

(ii) The Nodal District Collector is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.

(iii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued after finalising plans & estimates. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported as sanctioned in column No. 3

अनुबंध—5

सं०सी/56/2000–एमपीलैड्स दिनांक : 23 जनवरी, 2001

सेवा में,

आयुक्त,

कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम,

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,

सभी जिले ।

विषय : सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का अवमोचन ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशों की मद सं0 2, पैरा 2.7 के साथ पढ़े गये परिशिष्ट–2 के आंशिक सुधार के रुप में, निम्न संशोधन तत्काल लागू किए जाएंगें :–

पंजीकृत समितियों एवं न्यासों से संबंधित कार्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा :–

1. समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगे लाभार्थी संगठन, कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हों ।
2. लाभार्थी संगठन, प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त होना चाहिए । ऐसा संगठन प्रतिष्ठित है या नहीं, ये निर्णय, जिलाध्यक्ष द्वारा संगत कारकों जैसे सामाजिक सेवा/कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में निष्पादन, समग्र प्रतिष्ठा, अलाभकारी परिचालन, निष्पादन की पारदर्शिता तथा उसकी ठोस वित्तीय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा ।
3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियां, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाएंगी जो कि आम जनता के लिए पूर्णतः उपलब्ध होंगे । ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास निहित होगा ।
4. इन परिसंपत्तियों का विक्रय, हस्तांतरण, व्ययन सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।
5. इन निर्मित परिसंपत्तियों का रख–रखाव एवं व्यवस्था लाभार्थी संगठनों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी एवं सरकार उनकी आवधिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण करेगी ।
6. लाभार्थी संगठन वार्षिक रिपोर्ट एवं अपने परीक्षित लेखे नियमित रुप से सरकार को प्रस्तुत करेंगे ।
7. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियां, लाभार्थी संगठनों को वितरित किए जाने से पूर्व उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए लाभार्थी संगठनों को सरकार के साथ पहले ही एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।

भवदीय,

ह0

(वी. के. अरोड़ा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. माननीय सदस्य, राज्य सभा एवं लोक सभा ।
2. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा ।
3. मुख्य सचिव/प्रशासक, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ।
4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों से जुड़े सचिव, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ।

निम्न को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री (सां. एवं का.का.) ।
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सां. एवं का.का.)

Appendix-5

No. C/56/2000-MPLADS

23rd January, 2001

To

Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi,
District Collector/District Magistrate/Dy.Commissioner,
All Districts

Sub: Release of MPLADS Funds

In partial modification of Item No.2, Appendix-2 read with Para 2.7 of the Guidelines on MPLADS, the following amendment will come into force with immediate effect:-

"The works belonging to registered societies and trusts may be taken up under MPLADS subject to the following conditions:-

(i) The beneficiary organisation, engaged in social service/welfare activities shall be in existence at least for three years.

(ii) The beneficiary organisation shall be well-established and reputed one. Whether such organisation is reputed or not should be decided by the District Head concerned on the basis of relevant factors like performance in the field of social service/welfare activities, overall reputation, non-profit operation, transparency of performance and its sound financial position.

(iii) The funds from MPLADS will be used for creation of durable assets which would always be available for public use at large.

(iv) The ownership of such assets would vest in Government. The sale/transfer/disposal of these assets will not be undertaken without the prior approval of the Government.

(v) The maintenance and upkeep of assets so created will have to be ensured by the beneficiary organisation in advance and the assets so created will be subject to periodical audit/inspection by the Government.

(vi) The beneficiary organisation will submit to Government annual report and its audited accounts on regular basis.

(vii) The beneficiary organisation must enter into a formal agreement in advance with the Government to comply with the above conditions before the funds from MPLADS are disbursed to it.

Yours faithfully,
Sd./-
(V.K. ARORA)
Director (MPLADS)

Copy for information to:-

1. Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha.
2. Secretary-Generals, Rajya Sabha/Lok Sabha.
3. Chief Secretary/Administrator, all States/UTs.
4. Secretary dealing with MPLADS, all States/UTs.

Copy for information also to:-

1. PS to MOS (S&PI)
2. Sr. PPS to Secretary (S&PI)

821SP1/02-5

सं0सी/56/2000–एमपीलैड्स

दिनांक: 20 मार्च, 2001

सेवा में,

आयुक्त,

कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम,

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,

सभी जिले ।

विषय : एमपीलैड्स निधियों का अवमोचन ।

मुझे उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2001 का संदर्भ लेने के निदेश प्राप्त हुए हैं ।

2. उपरोक्त उद्धरत परिपत्र के उप–पैरा (7) के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाए :–

(7) एमपीलैड्स के दिशा निर्देशों के अंतर्गत दी गई कार्य नीति के अनुसार अनुमेय स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग करने से पूर्व उपरोक्त शर्त का अनुपालन करने हेतु लाभार्थी संगठन को सरकार के साथ आवश्यक रुप से पहले ही एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

भवदीय,

ह0

(वी. के. अरोड़ा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. माननीय सदस्य, राज्य सभा एवं लोक सभा ।
2. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा ।
3. मुख्य सचिव/प्रशासक, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ।
4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों से जुड़े सचिव, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ।

निम्न को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री (सां. एवं का.का.) ।
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सां. एवं का.का.)

ह0

(वी. के. अरोड़ा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

No. C/56/2000-MPLADS 20th March, 2001

To

Commissioners,

Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi,

District Collector/District Magistrate/Dy.Commissioner,

All Districts

Sub: Release of MPLADS Funds

I am directed to refer to this Ministry's Circular of even number dated 23rd January, 2001 on the above subject.

2. For sub-paragraph (vii) of the above mentioned circular, the following may be substituted:-

"(vii) The beneficiary organisation must enter into a formal agreement, in advance, with the Government to comply with the above condition before the funds from MPLADS are used for creation of durable assets permissible, as per procedure laid down under the MPLADS Guidelines".

Yours faithfully,

Sd./-

(V.K. Arora)

Director (MPLADS)

Copy for information to:—

5. Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha.

6. Secretary-Generals, Rajya Sabha/Lok Sabha.

7. Chief Secretary/Administrator, all States/UTs.

8. Secretary dealing with MPLADS, all States/UTs.

Copy for information also to:—

3. PS to MOS (S&PI)

4. Sr. PPS to Secretary (S&PI)

Sd./-

(V.K. ARORA)

DIRECTOR (MPLADS)

अनुबंध–6

सं0सी/50/2000–एमपीलैड्स

दिनांक: 22.01.2001

सेवा में,

सभी माननीय सांसद,

लोक सभा एवं राज्य सभा

विषय : केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के योगदान की एवज में एमपीलैड्स निधियों का उपयोग ।

महोदय/महोदया,

कृपया योजना आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं0 एम/12.043/10/2000–पी सी, दिनांक 27–12–2000 की संलग्न प्रतिलिपि को देखने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिशा निर्देशों में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के योगदान की एवज में एमपीलैड्स निधियों के उपयोग से संबंधित संशोधन की सूचना दी गई है । केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए एमपीलैड्स निधियों से ऐसे योगदान केवल उन्हीं कार्यों के लिए प्रयोज्य होंगे जो कि एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत आते हों तथा जिनसे एमपीलैड्स के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो ।

भवदीय

ह0

(वी. के. अरोड़ा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि :–

1. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
2. आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली ।
3. सभी जिला कलेक्टर/जिलाधिकारी/उप आयुक्त ।
4. योजना आयोग (योजना समन्वय प्रभाग) ।

APPENDIX-6

No.C/50/2000-MPLADS 22/01/2001.

To

All Hon'ble MPs of Lok Sabha/

Rajya Sabha.

Subject:- Using MPLADS funds towards contribution of State Governments in the Centrally Sponsored Schemes.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed herewith a copy of OM No.M-12043/10/2000-PC dated 27.12.2000 from the Planning Commission, intimating the amendment to the guidelines of the Centrally Sponsored Schemes for using MPLADS funds towards contribution of State Governments in Centrally Sponsored Schemes. Such contribution from MPLADS funds for CSS will be applicable only for those works which are covered under the MPLAD Scheme and subject to the compliance of guidelines on MPLADS.

Yours faithfully,

Sd./-

(V.K. ARORA)

Director

Copy to:—

1. Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of UTs.
2. Commissioner, Municipal Corporation of Calcutta/Chennai/Delhi.
3. All District Collectors/District Magistrates/Dy.Commissioners.
4. Planning Commission (Plan Coordination Division).

सं0 एम–12043/10/2000–पीसी

भारत सरकार

योजना आयोग

(योजना समन्वय प्रभाग)

योजना भवन

संसद मार्ग

नई दिल्ली–110001

दिनांक: 27.12.2000

कार्यालय ज्ञापन

दिशा निर्देशों में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सी एस एस) के लिए राज्य सरकारों के योगदान की एवज में एमपीलैड्स निधियों के उपयोग के लिए नीति दिशा निर्देशों में संशोधन संबंधी मुद्दे पर 13 नवंबर, 2000 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में हुई आंतरिक योजना आयोग की बैठक में विचार किया गया तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के दिशा निर्देशों में निम्न रुप में संशोधन किए जाने पर सहमति प्रकट की गई :

क. यदि कोई संसद सदस्य अपने क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रारंभ करना चाहता है तथा राज्य के योगदान की एवज में एमपीलैड्स के अपने आबंटन में से निधियों का प्रावधान करना चाहता है , तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की शेष निधियों को पूरा करने हेतु उन योजनाओं के लिए आवश्यक केंद्रीय सहायता केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दी जा सकती है ।

ख. इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए एमपीलैड्स निधियों की सहभागिता विशेष रुप से एमपीलैड्स के अधीन कार्यकारी अभिकरण एवं संबंधित सांसद द्वारा कार्य की अनुशंसा के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाएगी ।

2. यह वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

ह0

(एन. सी. सक्सेना)

सचिव

सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ ।

1. मंत्रिमण्डल सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।

2. सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली ।

No. M-12043/10/2000-PC

Government of India

Planning Commission

(Plan Coordination Division)

Yojana Bhawan,

Sansad Marg,

New Delhi - 110001.

Dated 27.12.2000

OFFICE MEMORANDUM

The issue of amendments to the policy guidelines for using MPLAD Scheme funds towards contribution of State Governments in the Centrally Sponsored Schemes (CSS) was considered in the Internal Planning Commission Meeting held on 13th November, 2000 under the Chairmanship of the Deputy Chairman, Planning Commission and it was agreed to amend the guidelines for CSS as under:

(a) If a Member of Parliament wants to undertake Centrally Sponsored Schemes in his/her area and decides to provide funds from his/her allocations under MPLADS as a substitute for State contribution, then the necessary Central Assistance to meet the balance of the CSS funds could be provided by the Central Ministries for those Schemes.

(b) The sharing of MPLADS funds for CSS would be further governed by the general guidelines issued by the Ministry of Statistics and Programme Implementation from time to time, particularly with regard to the implementing agency under MPLADS and recommendation of work by the concerned MP.

2. This issues with the approval of the Finance Minister.

Sd/-

(N.C. SAXENA)

Secretary

Secretaries of all Central Ministries/Departments.

Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of UTs.

Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Copy for information to:—

(i) Cabinet Secretary, Rashtrapathi Bhawan, New Delhi.

(ii) Secretary to PMO, South Block, New Delhi.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

No.C/56/2000-MPLADS

Dated 04/05/02

To

Commissioner,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi,
District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner,
All Districts.

Subject: Agreement to be entered into with Registered Societies and Trusts.

Sir/Madam,

Your kind attention is invited to our letter of even number dated 30.4.2001 forwarding therewith a copy of the draft agreement to be entered into with the registered societies/trusts. Clause 13 of the agreement required registration of the agreement under the Indian Registration Act in respective districts after affixing stamps required for registering the agreement. The stamp duty was to be borne by the beneficiary organisation. Representations have been received from some MPs about the payment of stamp duty by the beneficiary organisation. The matter has been reconsidered in consultation with the concerned authorities including the Ministry of Law and it is stated that the Agreement can be registered under the Registration Act on a non-judicial stamp paper of Rs. 10 or more which may vary from State to State. The stamp duty is not required to be paid in this case. Thus the document which is compulsorily registrable under Act 17 of Indian Registration Act may be got registered on non judicial paper of Rs. 10 or more as may be required in the State concerned.

Indian

Accordingly, a revised draft agreement is enclosed herewith, which may be put to use in the appropriate cases.

Yours faithfully,

(V.K. Arora)
Director

Copy to:

(iv) Hon'ble MPs of Rajya Sabha/Lok Sabha
(v) Shri Tapas Das Gupta, Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001
(vi) Shri R.N. Kalra, Director (CPPS), Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.

Draft Agreement

This Agreement is made on _____ between the Governor of _____ acting through the District Head (this includes District Collector, District Magistrate, Deputy Commissioner), Chief Executive of Municipal Corporation of Delhi/Kolkata/Chennai, (hereinafter called the "First Party"/the "Disbursing Authority") of the First Part AND the Chief Executive of the XY Registered Society/Registered Trust, (hereinafter called the "Second Party" of the Second Part.

(A) WHEREAS the First Party as the Head of the District Administration/Chief Executive of Municipal Corporation is the authority to get the development works implemented in the district//within the limits of the Municipal Corporation based on the locally felt needs on the recommendation of the Member of Parliament as per Guidelines on Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS).

**

(B) AND WHEREAS the Second Party is a Society, registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Trust, registered under the Indian Trust Act, 1882 is engaged in social service/welfare activities since more than _____years and is well established and reputed one in the field of social service/welfare activities with non-profit operation and with sound financial position.

(**Inapplicable portion may be deleted)

NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED between both the Parties to this Agreement and bind themselves to the following terms and conditions:-

1. The First Party shall undertake construction of _____ on the recommendation of the Member of Parliament as per the Guidelines on Member of Parliament Local Area Development Scheme, as amended from time to time (hereinafter referred to as MPLAD Scheme) for implementation of the work under the aforesaid MPLAD Scheme.

2. The Second Party will be eligible to receive and manage the assets created out of the funds by the First Party from the Member of Parliament Local Area Development Scheme as per the Guidelines on the subject meant for the benefit and use by and/or for the public at large.

3. A work at _____ regarding construction of _____ costing the value mutually agreed upon by the parties and that has been duly recommended by _____ (the name of concerned MP) under the MPLAD Scheme, shall be undertaken by the First Party, to be handed over to the Second Party after completion of the construction.

4. The First Party shall call for the necessary records from the Beneficiary Organisation such as the Memorandum of Association of the Society with special reference to Section 13 of the Societies Registration Act, 1860 and the trust deed of the trust with special reference to Section 77 and Section 78 of the Trust Act and be satisfied with the existence and reputation of the organisation, and its functioning as non-profit operations, transparency of performance, its sound financial position and its overall public reputation.

5. The Second Party shall give a declaration to the First Party to the effect that the Organisation it represents is a live organisation continuously functioning at least for the last three years engaging itself in Social Service and/or Welfare Activities.

6. The Second Party shall also give a declaration the First Party, that the land and immovable property offered by the Second Party to the First Party for executing the developmental work is free from any encumbrances, free from pending litigation and not affected by the Urban Land (Ceiling and Regulation)Act, 1976.

7. The Second Party shall also give a declaration to the First Party, that the assets created out of MPLADS funds for the society _____ or trust, is free from any encumbrances.

8. The Second Party shall ensure that durable assets, created out of MPLAD funds in the properties offered by the Second Party, must always be available for the use of or by the general public at large.

9. The State Govt. shall always and at all times be the absolute owner of the durable asset created out of the MPLAD funds.

10. The Second Party shall not sell/transfer/or otherwise dispose of any interest in or of such asset created out of MPLAD Scheme without the prior

written approval of the State Govt. After the written approval of the Government, the sale proceeds of the assets shall always vest and belong to the first party in all circumstances.

11. The Second Party herein undertakes the full responsibility to ensure maintenance and upkeep of the asset which will be subject to periodical audit and inspection by the First Party or any of its representative/nominee duly authorised in this behalf.

12. The Second Party shall submit to the First Party, annual report and its audited accounts on regular basis and within _____ days of the end of the Financial Year.

13. Since this indenture creates a future interest in the immovable property of the value of more than Rs. 100/- this Agreement be registered under Registration Act in the respective district.

14. In this indenture, wherever such an interpretation would be required to give the fullest possible scope and effect to the terms of the Agreement herein contained, the expressions District Head/Chief Executive and the Society or Trust shall include their respective successors or permitted assignees (Assignees).

IN WITNESS WHEREOF the parties here-to-have through their duly authorised representative executed this Agreement on day and year here-in-above-written.

Executed for and on behalf of the Governor of _____, by the District Head (District Collector/District Magistrate/ Deputy Commissioner)/Chief Executive of the Municipal Corporation.

by

In presence of following witnesses:

1._____

2._____

Executed for and on behalf of the Beneficiary Organisation/Second Party by _____ having authority to sign and execute this Agreement vide resolution dated _____ of _____,

In presence of following witnesses:

1._____

2._____

Member of Parliament Local Area Development Scheme

V. K. ARORA
DIRECTOR
TEL. : 3344938

सत्यमेव जयते

महिला सशक्तिकरण वर्ष
Women's Empowerment Year 2001

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

D.O. No. C/39/2000-MPLADS

Dated 21.2.2002

To

The Commissioner,
Corporation of Calcutta/Chennai/Delhi.
District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner,
all Districts.

Subject: **Contingent expenditure to execute MPLADS works**

Sir/Madam,

The works under MPLADS are implemented by the District Collector concerned by following the established procedure of the State Government. No funds are given to District Collectors or the State Government for implementing the Scheme and they are to manage the scheme with their own funds. Requests have been received that some funds as contingency for use in implementation of the scheme may be allowed to the District Collectors.

2. The matter has been considered in consultation with the Lok Sabha/Rajya Sabha Committee on MPLADS. It has been decided to allow the District Collectors to utilise half per cent amount as contingent expenditure out of the annual allocation of each MP per year under MPLADS. This half per cent amount of the value of works sanctioned under MPLADS can be specifically mentioned along with the value of the works sanctioned under MPLADS in the sanction orders to be issued after preparation of estimates etc. as per established procedure of the State Government.

3. Such contingent expenditure can be allowed to meet the cost of following items:-

(i) Stationery
(ii) Office equipment like typewriter, computer
(iii) Payment of honorarium/overtime to the staff put on MPLADS works
(iv) Telephone/fax charges, postal charges only.

....2

4. The contingent expenditure must not be used for meeting the cost following items:-

(i) Purchase of any kind of furnishing for office
(ii) Renovation of office building
(iii) Purchase or subscription of mobile phones
(iv) Purchase of vehicles
(v) Cost of fuel for vehicles
(vi) Purchase of air-conditioners, refrigerators etc.

5. It is requested that a separate account for the contingent expenditu incurred during a year under MPLAD Scheme may be maintained and ma available for scrutiny by audit.

6. The provision contained in this letter shall come into force from the da of its issue.

Yours faithfull

(V.K. Aro
Director (MPLAD

Copy to:-

(i) Hon'ble Members of Parliament, Rajya Sabha /Lok Sabha.
(ii) Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat.
(iii) Chief Secretary/Administrator, all States/UTs.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

V.K.ARORA
DIRECTOR (MPLADS)
Tel:3344933
Fax:3364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

Dated 24/04/02

No.R/24/33/98-MPLADS

To

Commissioner,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi,
District Collector/District Magistrate/Dy. Commissioner,
All Districts.

Subject: Limit of Rs. 25 lakhs per work outlined in para 4.1 of the guidelines on MPLADS.

Sir/Madam,

Para 4.1 of the guidelines on MPLADS stipulate that "ideally it would be desirable that the MPs suggest individual works costing not more than Rs. 25 lakhs per work.

2. Clarifications have been sought from this Ministry as to whether the cost limit of Rs. 25 lakhs stipulated in para 4.1 of the guidelines is to be made applicable to each work of an institution or total cost of all the works for a particular institution. Clarifications have also been sought that if a registered society/trust runs more than one institution whether the limit of Rs, 25 lakhs is to be made applicable to the trusts/societies as a whole or each institution of the trust/society. Hon'ble MPs also allocate funds to a registered society/trust where they themselves are the President/Chairman or Member of the managing committee etc. or trustee of the registered society/ trust in question.

2,

3. The matter has been considered in consultation with Lok Sabha/Rajya Sabha Committee on MPLADS. It is clarified that (a) the limit of Rs. 25 lakhs stipulated in para 4.1 is to be made applicable to a trust/society as a whole if a particular society/trust has more than one institution , or more than one work for that institution i.e. from MPLADS not more than Rs. 25 lakhs for a particular society/trust can be spent and (b) the benefits of MPLAD Scheme would not be given to a registered society/trust if the MP giving the proposal is himself the President/Chairman or member of the Managing Committee etc. or trustee of the registered society/trust in question.

Yours faithfully,

(V.K. Arora)
Director

Copy to:

(i) Hon'ble MPs of Rajya Sabha/Lok Sabha
(ii) Shri Tapas Das Gupta, Director, Rajya Sabha Secretariat, Par House Annexe, New Delhi - 110 001
(iii) Shri R.N. Kalra, Director (CPPS), Lok Sabha Secretariat, Par House Annexe, New Delhi.

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364187, 3742139
E-mail : mpl@mpi.delhi.nic.in

No. L/25/38/94-MPLADS Dated 24/10/02

To

Commissioner,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi,
District Collector/District Magistrate/Dy. Commissioner,
All Districts.

Subject: ***Implementation of works under MPLADS – Clarification regarding implementing agency.***

Sir/Madam,

The Government has been requested to clarify whether managing committees of schools/ colleges/educational institutions can be engaged as implementing agencies for construction of buildings, under MPLADS, for these educational institutions.

2. In this regard, it is stated that in accordance with the provisions contained in para 2.1 of the guidelines, implementing agencies can be either Government or panchayti raj institutions or any reputed non governmental organisations which are considered by the district heads as capable of implementing the works satisfactorily.

3. It is accordingly clarified that any reputed non-governmental organisation, including managing committee of an educational institution can be an implementing agency for MPLADS works, if the Collector concerned considers it as capable of implementing the work satisfactorily.

Yours faithfully,

(V.K. Arora)
Director(MPLADS)

Copy to:

(i) *Hon'ble Members of Parliament of Rajya Sabha and Lok Sabha*
(ii) *Shri Tapas Das Gupta, Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001*
(iii) *Shri R.N. Kalra, Director (CPPS), Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.*
(iv) *Chief Secretaries/Administrators/Secretaries, Planning – All States/Uts.*

Member of Parliament Local Area Development Scheme

V. K. ARORA
DIRECTOR
TEL. : 3344933

सत्यमेव जयते

महिला सशक्तिकरण वर्ष
Women's Empowerment Year 2001

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

No.C/20/2000-MPLADS

Dated 28th October, 2002

To

The Commissioners,
Corporation of Calcutta/Chennai/Delhi

District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts

Subject: PURCHASE OF AUDIO-VISUAL AIDS OF EDUCATIONAL NATURE UNDER MPLADS

Sir/Madam,

Attention is invited to our letter of even number dated 26.5.2000 wherein provision for purchase of audio-visual aids of educational nature was included under MPLADS, subject to the condition that there is proper place and proper provision for the safe custody of these aids.

2. On the basis of feed back received this provision is being reviewed, It is requested that the details of the audio-visual aids for educational institution allowed under MPLADS may be furnished urgently to the Ministry in the following format:

S.No.	Name of the audio-visual aid	Use to which it is being put by the educational institution	Cost (Rs.)	Name of the Hon'ble MP, recommending it	Name of the educational institution	Name of the Supplier
1	2	3	4	5	6	7

3. In the meantime, recommendation for purchase of audio visual aids may be withheld till a final view is taken in the matter.

Yours faithfully,

(V.K. Arora)
Director (MPLADS)

Copy to Hon'ble MPs of Rajya Sabha and Lok Sabha.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

V. K. ARORA
DIRECTOR
TEL. : 3344938

महिला सशक्तिकरण वर्ष
Women's Empowerment Year 2001

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATI
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

No. C/17/2002-MPLADS

Dated .....
20th November, 2002

To

Commissioner,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi.
District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner,
All Districts

Sub: **Inclusion of an additional item in the Illustrative List of works that can be taken up under MPLADS**

Sir/Madam,

The following may please be added at Sr.No.30 in the Illustrative List of works that can be taken up under MPLADS appearing as Appendix-1 in the Guidelines:-

"Purchase of computers for Government libraries".

Yours faithfully,

(V.K. Arora)

Copy to:-

1. Hon'ble MPs of Rajya Sabha and Lok Sabha.
2. Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs
3. Shri Tapas Das Gupta, JS, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi-110001
4. Shri R.N. Kalra, Director, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi-110001

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

सं0 सी/17/2002-एमपीलैड्स

Dated .....दिनांक 20 नवम्बर, 2002

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मेजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की व्याख्यात्मक सूची में एक अतिरिक्त मद का समावेश ।

महोदय/महोदया

दिशा-निर्देशों में परिशिष्ट-1 पर दी गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की व्याख्यात्मक सूची में निम्नलिखित को क्रम सं0 30 पर जोड़ा जाए :-

"सरकारी पुस्तकालयों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद"

भवदीय,

(वी0 के0 अरोड़ा)

प्रतिः

1. राज्य सभा और लोक सभा के माननीय सांसद
2. सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक
3. श्री तापस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन सौंध
4. श्री आर0 एन0 कालरा, निदेशक लोक सभा सचिवालय, संसद भवन सौंध, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

No. R/13/30/2002-MPLADS

Dated 15.12.2003

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi.
District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts.

Sub: Amendment to the Guidelines on MPLAD Scheme.

Sir/Madam,

Para 3.9 of the Guidelines on MPLADS shall be substituted with immediate effect as indicated below:-

Para 3.9 – **"All works for which recommendations are received in the Office of the District Head till the last date of the term of the MP are to be executed, provided these are as per norms and within the entitlement of the MPLADS funds of the MP."**

Yours faithfully,

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS)
Tel: 2336 7128

Copy for information to:-

1. Hon'ble Members of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha
2. Secretary-Generals, Rajya Sabha/Lok Sabha
3. The Chief Secretary/Administrator, all States/UTs
4. Secretary dealing with MPLADS, all States/UTs
5. Shri Tapas Dasgupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.
6. Shri A.S. Chera, Deputy Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.

Copy for information also to:
1. PS to MOS (S&PI)
2. Senior PPS to Secretary (S&PI)

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS)

Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATI
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

सं0 आर/13/30/2000–एमपीलैड्स

Dated .... दिनांक : 15 दिसंबर, 2003

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
जिला कलेक्टर/जिलाधीश/उपायुक्त,
सभी जिले ।

विषय : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों के पैरा 3.9 को निम्नानुसार तत्काल रूप से प्रतिस्थापित किया जाए :–

पैरा 3.9– "सभी कार्य जिनके लिए अनुशंसाएं संसद सदस्य के कार्यकाल की अंतिम तिथि तक जिलाध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्त हों, को कार्यान्वित किया जाए, बशर्ते ये प्रतिमानकों के अनुरूप और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों की पात्रता के अंतर्गत हों ।

भवदीय,

अबरार हुसैन

(अबरार हुसैन)
उप सचिव (एमपीलैड्स)
दूरभाष : 2336 7128

प्रति सूचनार्थ :–

1. राज्यसभा और लोकसभा के माननीय सदस्य ।
2. राज्य सभा/ लोक सभा के महासचिव ।
3. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक
4. सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबद्ध सचिव ।
5. श्री तापस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन सौंध, नई दिल्ली ।
6. श्री ए. एस. चेरा, उप सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन सौंध, नई दिल्ली ।

प्रति निम्नालिखित को भी सूचनार्थ :–

1. राज्य मंत्री (सां0 और का0का0) के निजी सचिव ।
2. सचिव (सां0 और का0का0) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

अबरार हुसैन

(अबरार हुसैन)
उप सचिव (एमपीलैड्स)

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

Dated ... 12.01.2004

No. C-03/2004-MPLADS

To,
The Chief Secretaries/Administrators,
Of all States/Union Territories,

The District Collectors/Deputy Commissioners/
District Magistrates of all Districts.

Subject: Amendment to the Guidelines on MPLADS

Sir/Madam,

Request has been received for the construction of shopping complex/market complex/market yards under MPLADS. The construction of shopping complex/market complex /market yards for private and commercial organizations, even though if it is for the benefit of the public, is not permissible under the MPLAD Scheme. Considering the benefit accrued through such works by the Local Bodies (Panchayats/Municipalities) and Government Organisations, it has been decided to allow construction of shopping/market complex and market yards for Panchayat/Municipality. Accordingly, the following shall be added as Item No: 32 in the illustrative list of works that can be taken up under MPLADS, given at Appendix-I of the Guidelines:

Item 32 " Works relating to the construction of shopping complex/market complex/market yards by and for Local Bodies (Panchayats/Municipality)"

Yours faithfully,

12-1-2004
(Ramesh Chandra Panda)
Additional Secretary

Copy to:-

1. Hon'ble Members of Parliament, Lok Labha & Rajya Sabha.
2. Chief Secretary/Administrator, All States/Uts.
3. Secretary dealing with MPLADS (All States/Uts)
4. Shri Tapas Das Gupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliamanet House Annexe, New Delhi-110001.
5. Shri A.S.Chera, Deputy Secretary, Lok Sabha Secretriat, parliament House Annexe, New Delhi-110001.

12-1-2004
(Ramesh Chandra Panda)
Additional Secretary

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

सत्यमेव जयते

Dated ....

सं0 सी/03/2004–एमपीलैड्स

दिनांक : 12.01.2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य सचिव/प्रशासक,
सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट,
जिला कलेक्टर/उपायुक्त ।

विषय : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत शॉपिंग काम्पलेक्स/मार्किट कॉम्पलेक्स/मार्किट यार्ड के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है । निजी एवं वाणिज्यिक संगठनों के लिए शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मार्किट कॉम्पलेक्स/मार्किट यार्ड का निर्माण, हालांकि जनता के लाभ के लिए होता है, लेकिन यह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं है । ऐसे कार्यों से स्थानीय निकायों (पंचायतों/नगर पालिकाओं) एवं सरकारी संगठनों को हुए लाभों को देखते हुए पंचायत/नगर पालिका के लिए शॉपिंग/मार्किट काम्पलेक्स एवं मार्किट यार्डों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, निम्न को दिशा–निर्देशों के परिशिष्ट–1 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की व्याख्यात्मक सूची में मद सं0 32 के रूप में जोड़ा जाएगा ।

मद 32 " स्थानीय निकायों (पंचायतों/नगर पालिकाओं) द्वारा एवं उनके लिए शापिंग काम्पलेक्स/मार्किट कॉम्पलेक्स/मार्किट यार्ड के निर्माण संबंधी कार्य"

भवदीय,

र.च. पाण्डा [illegible]

(रमेश चन्द्र पांडा)
अपर सचिव, भारत सरकार

प्रति:–

1. माननीय संसद सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक।
3. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित सचिव (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) ।
4. श्री तपस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली–110001
5. श्री ए.सी. चेरा, उप सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली–110001

र.च. पाण्डा [illegible]

(रमेश चन्द्र पांडा)
अपर सचिव, भारत सरकार

डा. विजय प्रकाश गोयल
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL
DIRECTOR
TEL : 23364206 / 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
कमरा नं.-209, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
R. NO. 209, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

No.L/6/16/94-MPLADS

Dated 15/01/2004.

To

The Commissioner,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi,
District Collector/District Magistrate/
Deputy Commissioner, All Districts.

Subject:- AMENDMENTS TO GUIDELINES ON MPLAD SCHEME.

Sir/Madam,

The following amendments to Guidelines on MPLAD Scheme is notified with immediate effect:-

2. The following shall be added as Item No.31 in the illustrative list of works that can be taken up under MPLADS, given at Appendix-1 of the Guidelines:-

" 31. Works relating to installation/ procurement of pump set/ pumping machinery for drainage/sewage disposal facility ".

Yours faithfully,

(Vijay P. Goel)
Director (MPLADS)
Tele:-23344933

Copy to:-

1. Hon`ble Members of Parliament, Lok Sabha & Rajya Sabha.
2. Chief Secretary/Administrator, All States/UTs.
3. Secretary dealing with MPLADS (All States/UTs).
4. Shri Tapas Das Gupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001.
5. Shri A.S. Chera, Deputy Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

डा. विजय प्रकाश गोयल
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL
DIRECTOR
TEL : 23364205/23344933
FAX : 23364197
सत्यमेव जयते

सं0 एल/6/16/94–एमपीलैड्स

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
कमरा नं.-209, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -11000
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATI
R. NO.-209, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-11000
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

Dated .....

दिनांक: 15.01.2004

सेवा में,
आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम,
सभी जिलों के
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देशों में किए गए निम्नलिखित संशोधन तत्काल आधार पर अधिसूचित किए जाते हैं:–

2. निम्न को दिशा–निर्देशों के परिशिष्ट–1 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की व्याख्यात्मक सूची में मद सं0 31 के रूप में जोड़ा जाएगा ।

" 31. जल निकास/ मल जल निकास सुविधा के लिए पम्पसेट/पम्पिंग मशीनरी के संस्थापन/प्रापण से संबंधित कार्य"

भवदीय,

(विजय प्रकाश गोयल)
निदेशक (एमपीलैड्स)
दूरभाष : 23344933

प्रति :–

1. माननीय संसद सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक।
3. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित सचिव (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) ।
4. श्री तपस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली– 110001
5. श्री ए.सी. चेरा, उप सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली–110001

001

ATION
001

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

No. C/11/2002-MPLADS

Dated 5.2.2004

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi.
District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts.

Sub: **Amendment to the Guidelines on MPLAD Scheme**

Sir/Madam,

The demand for the construction of libraries for legal practitioners (Bar) in the country with MPLAD fund has been coming to the Government from Members of Parliament. The existing guidelines on MPLAD Scheme provide for the construction of libraries for educational institutions belonging to Government or local bodies and also to aided institutions and unaided but recognized institutions provided the institution has been in existence for not less than 2 years. Construction of public libraries and reading rooms are also permissible.

2. Keeping in view the demand made in this regard, it has been decided that the construction of libraries for legal practitioners may also be allowed with some conditions. Accordingly, the following shall be added as item No. 33 in the Illustrative List of Works that can be taken up under MPLAD Scheme, given at Appendix 1 of the Guidelines on MPLADS:

"33 Construction of Bar (legal practitioners) libraries provided (i) such libraries, while essentially for use by members of the Bar, are also open to the members of the Court, Bench, Law students and others interested; and (ii) the ownership of the building of such libraries vests with the Government/Local Body/Courts and registered Societies or Bar Associations but not with private associations."

Yours faithfully,

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS)
Tel: 2336 7128

Copy to:-

1. All MPs.
2. The Chief Secretary/Administrator (All States/UTs).
3. The Secretary, Planning/Rural Development, Department, All States/UTs.
4. Shri Tapas Dasgupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.
5. Shri Devender Singh, Director, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

सं0सी/11/2002–एमपीलैड्स

Dated ..... दिनांक: 5.2.2004

सेवा में,

आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम
जिला कलेक्टर/जिला मेजिस्ट्रेट/उपायुक्त,
सभी जिले

विषय: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से देश में लीगल प्रैक्टीशनर्स (बार) के लिए पुस्तकालयों के निर्माण की मांग सांसदों की ओर से सरकार के पास आ रही है । सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी विद्यमान दिशा–निर्देशों में, सरकारी अथवा स्थानीय निकायों के शैक्षिक संस्थानों तथा सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए भी पुस्तकालयों के निर्माण का प्रावधान है बशर्ते कि उक्त संस्थान 2 वर्ष से कम पुराना न हो । सार्वजनिक पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण भी अनुमेय है ।

2. इस संबंध में की गई मांग को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कुछ शर्तों के साथ लीगल प्रैक्टीशनर्स के लिए भी पुस्तकालयों के निर्माण की अनुमति दी जाए । तदनुसार निम्नलिखित को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों के परिशिष्ट 1 पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्यों की दी गई व्याख्यात्मक सूची में मद सं. 33 के रूप में शामिल किया जाए ।

"बार (लीगल प्रेक्टीशनर्स) पुस्तकालयों का निर्माण, बशर्ते (1) ऐसे पुस्तकालय अनिवार्य रूप से बार के सदस्यों के साथ–साथ कोर्ट, बैंच, विधि–विद्यार्थियों एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों के उपयोगार्थ भी होंगे एवं (2) ऐसे पुस्तकालयों के भवनों का स्वामित्व सरकार/स्थानीय निकाय/न्यायालयों एवं पंजीकृत समितियों अथवा बार ऐसोसिएशन के पास होगा, लेकिन निजी ऐसोसिएशन के पास नहीं ।"

भवदीय,

अबरार हुसैन

(अबरार हुसैन)
उप सचिव (एमपीलैड्स)
दूरभाष : 23387128

प्रति :

1. सभी संसद सदस्य ।
2. मुख्य सचिव/(सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों) के प्रशासक ।
3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिव, योजना/ग्रामीण विभाग ।
4. श्री तपस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक, लोक सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।

अबरार हुसैन

(अबरार हुसैन)
उप सचिव (एमपीलैड्स)
दूरभाष : 23387128

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATIC
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@... delhi.nic.in

NTATION

सत्यमेव जयते

No. R/13/28/2003-MPLADS

Dated 14-05-2004

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi.
District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts and the Chairman, DDA, New Delhi.

Sub: **Implementation of works under MPLAD Scheme.**

Sir/Madam,

A clarification was given in this Ministry's letter No. L/10/20/94-MPLADS, dated 16.1.199 (copy enclosed) that any work, once taken up on the recommendation of the MP, should not b stopped/abandoned in between as by that time some expenditure might have been incurred an stoppage of work at that stage would lead to infructuous expenditure and delay on account c preparing fresh estimates.

2. A question has been raised whether a work recommended by the MP and sanctioned by the District Collector, can be cancelled if no expenditure is incurred. This question has been considerec in detail. The following clarifications are issued:-

"On receipt of the recommendation of the MP, the Collector examines it in the light of Guidelines and if finds the proposed work is permissible, gets detailed estimates prepared by the technical authorities and after getting consent of the MP to the estimated amount, the sanction for execution of the works is issued. In this process, sufficient time and labour is utilised. Any change in the work will delay the works execution and will not be in the public interest. It has, therefore, been decided that works, once recommended and sanctioned under MPLAD Scheme, will not be cancelled irrespective of whether any funds have been spent or not or the work had started or not."

3. This Ministry's letter No. L/10/20/94-MPLADS dated 16.1.96 may be treated as amended to that extent.

Yours faithfully,

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS)
Tel: 2336 7128

Copy to:-

1. All MPs.
2. The Chief Secretary/Administrator (All States/UTs).
3. The Secretary, Nodal Department dealing with MPLADS (All States/UTs).
4. Shri Tapas Dasgupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.
5. Shri Devendra Singh, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.

(Abrar Hussain)
Deputy Secretary (MPLADS

सं0आर/13/28/2003–एमपीलैड्स

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3364197, 3742138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

Dated 14-05-2004.

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम,
सभी जिलों के
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, और
अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

विषयः <u>संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन</u>

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के पत्र संख्या एल/10/20/94–एमपीलैड्स दिनांक 16.1.1996 द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि सांसद की अनुशंसा पर शुरू किए गए किसी भी कार्य को बीच में बंद/छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस समय तक कार्य में कुछ व्यय हो चुका होगा और उस स्थिति में उस कार्य को बंद करने से निष्फल व्यय होगा और नए अनुमान तैयार करने से कार्य में विलंब होगा ।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या यदि कोई व्यय न किया गया हो तो सांसद द्वारा अनुशंसित और जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कार्य रद्द किया जा सकता है । इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। निम्न स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :–

सांसद की अनुशंसा प्राप्त होने पर कलेक्टर दिशा–निर्देशों के अनुसार उसकी जांच करता है और कार्य को स्वीकार्य पाने पर तकनीकी प्राधिकारियों से विस्तृत प्राक्कलन तैयार करवाता है और अनुमानित राशि के लिए सांसद की सहमति प्राप्त करने के बाद कार्य के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति जारी की जाती है । कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से कार्य के कार्यान्वयन में विलंब होगा और यह लोकहित में नहीं होगा । इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित एवं स्वीकृत कार्य रद्द नहीं किया जाएगा चाहे उस कार्य पर कोई व्यय हुआ हो या नहीं अथवा कार्य शुरू हुआ हो या नहीं ।

3. इस मंत्रालय के पत्र सं0 एल/10/20/94–एमपीलैड्स दिनांक 16.1.96 को उक्त सीमा तक यथा संशोधित माना जाए ।

भवदीय,
अबरार हुसैन
(अबरार हुसैन)
उप सचिव, (एमपीलैड्स)
दूरभाष: 23387128

प्रतिलिपि:

1. सभी सांसद ।
2. मुख्य सचिव/प्रशासक (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) ।
3. सचिव, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) का कार्य करने वाले सभी केंद्रक विभाग ।
4. श्री तापस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, लोक सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।

अबरार हुसैन
(अबरार हुसैन)
उप सचिव,(एमपीलैड्स)

No.L/10/20/94-MPLADS
Government of India
Department of Programme Implementation

Sardar Patel Bhavan, New Delhi
Dated 16th January, 1996

To

All District Collectors/
Deputy Commissioners/
District Magistrates.

Subject: Implementation of MPLADS works.

.....

Sir,

It has been brought to the notice of this Department that some MPs request the implementing agencies and/or the Collectors to stop a particular work half-way and take up some other work, instead. It is not desirable to stop the works once they are taken up. In this connection, it is advised that any work once taken up on the recommendation of the MP should not be stopped/abandoned in-between as by that time some expenditure would have been incurred and stoppage of work at that stage would lead to infructuous expenditure and delay on account of preparation of fresh estimates. You may accordingly like to issue instructions to the field agencies not to stop any work in-between even if such course of action is recommended by the concerned MP. Whenever any MP approaches with such a request, he/she should be informed suitably and politely that works once sanctioned and started cannot be stopped or abandoned half-way.

Yours faithfully,

(V.K.ARORA)
Deputy Secretary to the Govt. of Indi

डा. विजय प्रकाश गोयल
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL
DIRECTOR
TEL : 23364205
FAX : 23364197
सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
कमरा नं.-209, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATIC
R. NO.-209, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

No. C/22/2004-MPLADS

Dated 26.5.2004

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi.
District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts and the Chairman, DDA, New Delhi.

Sub: Procedure for release of MPLADS funds.

Sir/Madam,

In accordance with para 4.4 of the Guidelines on MPLADS, the instalment of Rs.1 crore in respect of MP constituency would be released once the unsanctioned balance amount, after taking into account the cost of all works sanctioned, comes to less than Rs, 50 lakh. It has further been provided therein that the eligibility for the release of an instalment will be decided on the basis of Statement of Expenditure furnished by the concerned District Head in the format (Appendix –3 and 4). The formats at Appendix –3 and 4 have been revised and a copy each of them is enclosed with the request that in future, the requisite information may be furnished in that formats.

2. This Ministry has been following the aforesaid provisions for releasing the instalment of MPLADS funds. Photo copies/fax copies of the Statement of Expenditure and signed by any officer of the District Administration were being accepted for release of funds. This, however, does not conform to the standard release procedure of the Government of India.

3. In order to have proper check on release and ensure timely utilization of MPLADS funds, it has been decided that from current financial year 2004-05, the instalment of MPLADS fund will continue to be released on the basis of Statement of Expenditure, showing unsanctioned balance of less than Rs. 50 lakh. However, the Statement of Expenditure will be accepted only when it is in original, duly signed and sealed by the Head of the District Administration (District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner) or by the Chief Executive of the Municipal Corporation concerned. No photo copy or fax copy of the Statement of Expenditure or signed by any officer other than the Head of the District Administration or not sealed will be accepted in this Ministry for release of MPLADS fund.

Yours faithfully,

(Vijay P. Goel)
Director (MPLADS)

Copy to:-

1. All MPs.
2. The Chief Secretary/Administrator (All States/UTs).
3. The Secretary, Nodal Department dealing with MPLADS (All States/UTs).
4. Shri Tapas Dasgupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
5. Shri Devendra Singh, Director, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

डा. विजय प्रकाश गोयल I.S.S.
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL I.S.S.
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

सं0 सी/22/2004-एमपीलैड्स

Dated ..... दिनांक: 28.05.2004

सेवा में,

आयुक्त,
दिल्ली/चेन्नई/कोलकाता निगम,
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त एवं
अध्यक्ष, दि0 कि0 प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

विषय : सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के अवमोचन की प्रक्रिया ।

महोदय/महोदया,

सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 के अनुसार, किसी सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रूपए की किश्त, सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को जोड़ने के बाद अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रूपए से कम होने पर जारी की जाएगी । इसके अतिरिक्त उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रपत्र (परिशिष्ट-3 एवं 4) में प्रस्तुत व्यय विवरण के आधार पर किश्त के अवमोचन की पात्रता निर्धारित की जाएगी । परिशिष्ट-3 एवं 4 में दिए गए प्रपत्रों में संशोधन कर दिया गया है और प्रत्येक की प्रति इस अनुशेष सहित संलग्न की जा रही है कि भविष्य में अपेक्षित सूचना इन प्रपत्रों में भेजें ।

2. यह मंत्रालय सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के अवमोचन के लिए उपर्युक्त प्रावधानों का पालन कर रहा है । निधियों के अवमोचन के लिए जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व्यय विवरण की फोटो प्रतियों/फैक्स प्रतियों को स्वीकारा जा रहा था । तथापि, यह भारत सरकार की मानक अवमोचन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है ।

3. अवमोचन पर उचित जांच एवं सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 से सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों की किश्त का अवमोचन 50 लाख रूपए से कम अस्वीकृत शेष दर्शाने वाले व्यय विवरण के आधार पर ही होता रहेगा । तथापि, व्यय विवरण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब वह मूल रूप में होगा और जिला प्रशासन (जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त) के अध्यक्ष अथवा संबंधित नगर निगम के मुख्य अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सीलबद्ध होगा । व्यय विवरण की फोटो प्रति अथवा फैक्स प्रति अथवा जिला प्रशासन के अध्यक्ष के अलावा किसी और द्वारा हस्ताक्षरित अथवा जिसमें सील न लगी हो, को सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के अवमोचन के लिए स्वीकारा नहीं जाएगा ।

भवदीय,

विजय गोयल

(विजय पी. गोयल)
निदेशक (सां.स्था.क्षे.वि.यो.)

प्रति :

1. सभी सांसद ।
2. मुख्य सचिव/प्रशासक (सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र) ।
3. सचिव, सां.स्था.क्षे.वि.यो. से जुड़े सभी केंद्रक विभाग (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)
4. श्री तपस दासगुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, लोक सभा सचिववालय, संसदीय सौंध, नई दिल्ली ।

FORMAT FOR RELEASE OF FUNDS UNDER...

MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)
LOK SABHA

STATEMENT OF INFORMATION UNDER MPLADS (UP TODATE) dd-mm-yyyy

STATE :	CONSTITUENCY:
NODAL DISTRICT ADDRESS:	TELEPHONE NUMBERS: STD CODE OFFICE: RESIDENCE: FAX: MOBILE: e-mail

NAME OF MEMBER OF PARLIAMENT

10th LOK SABHA

11th LOK SABHA

12th LOK SABHA

13th LOK SABHA

14th LOK SABHA

PHYSICAL PERFORMANCE

Rs. in lakh

LOK SABHA	WORKS RECOMMENDED		WORKS SANCTIONED		WORKS COMPLETED		WORKS NOT COMPLETED	
	NUMBER	COST	NUMBER	COST	NUMBER	COST	NUMBER	COST
10th								
11th								
12th								
13th								
14th (2004 – 05)								
14th (2005 – 06)								
TOTAL								

FUNDS RECEIVED FOR THE CONSTITUENCY

FUNDS POSITION	YEAR	FUNDS RECEIVED (Rs. in lakh)
	1993-94	
	1994-95	
	1995-96	
	1996-97	
	1997-98	
	1998-99	
	1999- 2000	
	2000- 2001	
	2001- 2002	
	2002- 2003	
	2003- 2004	
	2004- 2005	
(a) Funds received from the Government of India	TOTAL	
(b) Amount of interest accrued on the funds		
(c) TOTAL (a + b)		
(d) Total cost of works sanctioned		
(e) Total Unsanctioned Balance (c - d)		
(f) Actual Expenditure		
(g) Total funds available with the District Administration (c –f)		

Dated:

Signature of the
District Collectot/District Magistrate/
Deputy Commissioner/CEO of Municipal Corporation
(Name in Capital Letters)
Designation
Seal

Copy to Member of Parliament

Note: (i) The Collector of the Nodal District is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.

(ii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued after finalising plans and estimates. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported.

निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त निधि

निधि का ब्योरा	वर्ष	प्राप्त निधियाँ रू0 लाख में
	1993–94	
	1994–95	
	1995–96	
	1996–97	
	1997–98	
	1998–99	
	1999– 2000	
	2000– 2001	
	2001– 2002	
	2002– 2003	
	2003– 2004	
	200– 2005	
	योग	
(क) भारत सरकार से प्राप्त निधि		
(ख) निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि		
(ग) योग (क + ख)		
(घ) स्वीकृत कार्यों की कुल लागत		
(च) जिले में उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष (ग–घ)		
(छ) वास्तविक व्यय		
(ज) जिले में उपलब्ध कुल निधि (ग–छ)		

दिनांक –

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/निगम के मु0का0अधि0 के हस्ताक्षर

नाम

पद

मोहर

संसद सदस्य को प्रतिलिपि

नोट:(1) केन्द्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना भी हो जो कि निर्वाचन क्षेत्र में आतें हैं जहाँ सांसद की अनुशंसा पर निधियां स्थानांतरित की गई ।

(2) स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए योजना एवं प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन मिला है, स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिये।

FORMAT FOR RELEASE OF FUNDS UNDER MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS) RAJYA SABHA

STATEMENT OF INFORMATION UNDER MPLADS (UP TODATE) dd-mm-yyyy

STATE :	**NODAL DISTRICT:**
NODAL DISTRICT ADDRESS:	**TELEPHONE NUMBERS:** **STD CODE** **OFFICE:** **RESIDENCE:** **FAX:** **MOBILE:** **e-mail**
NAME OF MP	

PHYSICAL PERFORMANCE

Rs. in lakh

YEAR-WISE	WORKS RECOMMENDED		WORKS SANCTIONED		WORKS COMPLETED		WORKS NOT COMPLETED	
	NUMBER	COST	NUMBER	COST	NUMBER	COST	NUMBER	COST
OTAL								

FUNDS RECEIVED FOR THE NODAL DISTRICT

FUNDS POSITION	YEAR	FUNDS RECEIVED (Rs. in lakh)
	1993-94	
	1994-95	
	1995-96	
	1996-97	
	1997-98	
	1998-99	
	1999- 2000	
	2000- 2001	
	2001- 2002	
	2002- 2003	
	2003- 2004	
	2004- 2005	
(a) Funds received from the Government of India	TOTAL	
(b) Amount of interest accrued on the funds		
(c) Amount received through distribution of the funds of the predecessor MP		
(d) TOTAL (a + b +c)		
(e) Total cost of works sanctioned		
(f) Total Unsanctioned Balance available with the District (d -c)		
(g) Actual Expenditure		
(h) Total funds available with the District Administration (d - g)		

Dated:

Signature of the
District Collectot/District Magistrate/
Deputy Commissioner/CEO of Municipal Corporation
(Name in Capital Letters)
Designation
Seal

Copy to Member of Parliament

Note: (i) The Collector of the Nodal District is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.

(ii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued after finalising plans and estimates. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported.

राज्य सभा के संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) के अंतर्गत निधियों के अवमोचन स्वीकृत कार्य तथा व्यय की सूचना हेतु प्रारूप

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सूचना विवरण (दिनांक .....तक)

राज्य	
केन्द्रक जिले का पता:	केन्द्रक जिला दूरभाष सं.– एस.टी.डी कोड सं.– कार्यालय – आवास – फैक्स – मेबाईल– ई. मेल
संसद सदस्य का नाम	

प्रत्यक्ष निष्पादन

रू0 लाख में

वार्षिक	अनुसंशित कार्य		स्वीकृत कार्य		पूर्ण किए गए कार्य		अधूरे कार्य	
	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत

केन्द्रक जिले के लिए प्राप्त निधि

निधि का व्योरा	वर्ष	प्राप्त निधियाँ रू0 लाख में
	1993-94	
	1994-95	
	1995-96	
	1996-97	
	1997-98	
	1998-99	
	1999- 2000	
	2000- 2001	
	2001- 2002	
	2002- 2003	
	2003- 2004	
	2004- 2005	
	योग	
(क) भारत सरकार से प्राप्त निधि		
(ख) निधियों पर अर्जित व्याज की राशि		
(ग) पूर्ववर्ती संसद सदस्यों द्वारा छोड़ी गई निधि के वितरण के फलस्वरूप प्राप्त राशि		
(घ) योग (क + ख + ग)		
(च) स्वीकृत कार्यों की कुल लागत		
(छ) जिले में उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष (ग–घ)		
(ज) वास्तविक व्यय		
(झ) जिले में उपलब्ध कुल निधि (घ–ज)		

दिनांक –

हस्ताक्षर
(जिला प्रमुख का नाम)
पद
मोहर

संसद सदस्य को प्रतिलिपि

नोटः(1) केंन्द्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना भी हो जो कि निर्वाचन क्षेत्र में आतें हैं जहॉ सांसद की अनुशंसा पर निधिया स्थानांतरित की गई ।

(2) स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए योजना एवं प्राकलनों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन मिला है, स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिये।

डा. विजय प्रकाश गोयल I.S.S.
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL I.S.S.
DIRECTOR
TEL : 23344033
FAX : 23384197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

No. C/22/2004-MPLADS

Dated 11.6.2004

To

All the District Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners
Commissioner, Municipal Corporation of Delhi/ Kolkata/Chennai
and the Chairman, DDA, New Delhi.

Sir/Madam,

In accordance with para 4.4 of the Guidelines on MPLADS, the next instalment of MPLADS funds is released by this Ministry on the basis of Statement of Expenditure, received in the prescribed proforma (Appendix 3 or 4 of the Guidelines) showing unsanctioned balance as less than Rs. 50 lakh. It is also provided in the Guidelines in para 4.2 that the release of funds will be made with reference to the actual progress achieved in expenditure and execution of works. Therefore, the actual expenditure figures are also being looked into and the next instalment will now be released only when the unspent balance is less than Rs. 1 crore.

2. The newly constituted 14th Lok Sabha includes some Members of Parliament who have come for the first time. In their cases, it would not be proper to wait for the availability of funds. It is, therefore, suggested that you may process and accord financial sanction to all the works which have been recommended by the new Members of Parliament and which are as per the norms of the Guidelines on MPLADS upto the full extent of their entitlement of funds without waiting for receipt of funds from this Ministry and continue to furnish the requisite monthly expenditure statement in the prescribed proforma regularly. This will assist us to process the release of funds from this Ministry without any interruption.

Yours faithfully,

(Vijay P. Goel)
Director (MPLADS)

Copy to:-

1. All MPs.
2. The Chief Secretary/Administrator (All States/UTs).
3. The Secretary, Nodal Department dealing with MPLADS (All States/UTs).
4. Shri Tapas Dasgupta, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
5. Shri Devendra Singh, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

डा. विजय प्रकाश गोयल I.S.S.
निदेशक
Dr. VIJAY P. GOEL I.S.S.
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATI
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : vijaypgoel@alpha.nic.in

सं.सी/22/2004-एमपीलैडस

Dated .....दिनांक 11.6.2004

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/आयुक्त, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई नगर निगम एवं दिल्ली वि प्राधिकरण के अध्यक्ष

महोदय/महोदया,

सा.स्था,क्षे.वि.यो.संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सां.स्था.क्षे.वि.यो.निधियों की अगली किस्त निर्धारित (दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट 3 अथवा 4) में, 50 लाख रु. से कम अस्वीकृत शेष को दर्शाने वाली व्यय विवरण आधार पर इस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है । दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 में यह भी प्रावधान है कि निधियों अवमोचन व्यय एवं कार्यों के कार्यान्वयन में हुई वास्तविक प्रगति के मद्दे नजर किया जाएगा । इसलिए वास्तविक के आंकड़ों की भी जांच की जा रही है और अब अगली किस्त अव्ययित शेष, एक करोड़ रु. से कम होने पर ही की जाएगी ।

2. नवगठित 14वीं लोकसभा में कुछ सदस्य पहली बार आए हैं । उनके मामलों में निधियों की उपलब्धता प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा । इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप नए संसद सदस्यों द्वारा उनकी नि की पात्रता की सीमा तक अनुशंसित सभी कार्यों में कार्रवाई करें और उनको वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें और मा व्यय विवरणी निर्धारित प्रपत्र में नियमित रुप से भेजते रहें । इससे इस मंत्रालय को बिना किसी अवरोध के निधि अवमोचन में सहायता मिलेगी।

भवदीय,

(विजय पी.गोयल)
निदेशक (एमपीलैडस)

प्रतिलिपि:-

1. सभी संसद सदस्य ।
2. मुख्य सचिव/प्रशासक (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) ।
3. सचिव, एमपीलैडस कार्यों से संबंद्ध केन्द्रक विभाग (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) ।
4. श्री तापस दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।